THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Now it is for Private Members' Bills... *(Interruptions).*

SHRI JOHN F. FERNANDES; The want to say.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): You please conclude.

SHRI JOHN F. FERNANDES: The Government must enquire into the matter and see that the culprits are punished.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Now we switch over to the Private Members' Resolution. .. .*{Interruptions).*

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Sir, excuse me. I want to clarify...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Dr. Jain, we have switched over to another business... *(.Interruptions).* Now I can't go back.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I just want to know what is to be token up after 5.00 p.m. After this is over, are we taking up the rest of the busin-ness which is listed on the agenda?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Yes. We will go according *to* the agenda. Please don't waste the time of Private Members. You wait.... *(Interruptions)..*

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: My point is, after this, will you take up the rest of the business listed in the agenda today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I am not going to say anything just now. Mr. Jadhav is on his legs. You ask your clarification at 5.00 p.m.

RESOLUTION RE; RISING PRICES— contd.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अमीन साहब ने जो यह रिजोल्यूशन लाया है कि –

"This House express its deep concern over the continuous rise in prices of all commodities in the country putting the common man in great distress and also over the addition to the inflationary spiral through issue of administrative orders, the latest example of which being the hike in the prices of petroleum products, and urges upon Government to take immediate comprehensive steps to arrest the continuing rise due to the economic policies, administered price hike and import of consumer items at the behest of the World bank."

तो उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि प्राइसेस में वृद्धि हुई है, मूल्यों में वृद्धि हुई है, मगर मैं इस बात से पूरी तरह से इंकार करता हूं कि—

the latest example of which being the hike in the prices of petroleum pro-ducts.

To take steps to arrest the continuing rise due to the economic policies, administered price hike and import of consumer items at the behest of the World Bank.

यह भी बात ठीक है ।

लेकिन यह जो आपने कहा है, उसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं क्योंकि उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें तो दो राय नहीं हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी माननीय सदस्यों ने टीका-टिप्पणी की है । माननीय, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें सीधे तरीके से यह कहा गया था कि सौ दिन में प्राइसेस कम करेंगे । मगर कुछ प्राइसेस में कमी नहीं आई, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, प्राइसेस ज

बढ़ी हैं हमारे देश में तो उसका पूरा दोष कांग्रेस सरकार पर लगाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके पहले की जो सरकार थीं, जनता दल की सरकार 11 महीने चली और और फिर 57 में से 42 मिनिस्टर्स की समाजवादी जनता पार्टी की सरकारे थी। उन्होंने जो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का मिस-मैनेजमेंट किया, उसकी वजह से कोई भी सरकार, चाहे मनमोहन सिंह हो या वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हो, अगर वह भी आए तो भी उस परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि

there has been confusion, what we say, confusion worse confounded, due to the misrule of the two previous Governments.

तो इसी वजह से प्राइसेस में वृद्धि हुई है। मगर पिछले कुछ दिनों में उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इस समाचार पत्रों को देखें तो हम देखते हैं कि इनफ्लेशन रेट में और प्राइसेस में कुछ कमी आई है।

सरकार उसके लिए जरूर प्रयास करती है, मगर सरकार के प्रयासों के बावजूद भी यह बात हमें बहुत अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि गत साल हमारा जो अन्न-धान्य का प्रोडक्शन था, अनाज का जो प्रोडक्शन था वह कम हो गया है। यह 176 मिलियन टन से गिरकर 169 8 मिलियन टन पर आ गया है, 170 मिलियन टन पर आ गया है। जब कृषि का उत्पादन कम होता है तो अनाजों की कीमतें बढ़ती हैं और कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो अनाज और सारी वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। हमारे देश की जो अर्थनीति है वह कृषि पर आधारित है। इसका मुख्य आधार, उसका जो रंभा है वह कृषि है। जब कृषि में घट होती है हमारे मूल्यों में वृद्धि होती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है तो हमारे मूल्यों में कमी होती जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से उसका बहुत कम संबंध है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जरूर सच है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अगर सारी दुनिया में पिछले एक साल का देखें तो मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह प्राइस राइज जो है इंटरनेशनल फिनोमिना है : अब यह दुनिय इतनी छोटी हो गई है कि कोई भी देश, चाहे हिन्दुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांगला देश हो, या अमरीका तक हो, कोई भी देश एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकता। अगर दुनियां में कहीं भी कुछ घटना है तो उसका असर दुनियां के किसी भी कोने तक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यह इंटरनेशनल फिनोमिना है और सारी दुनिया में मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिसका भारत में भी असर हुआ है। हमारी सरकार ने उस वृद्धि को रोकने का अच्छी तरह से प्रयास किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, जिसका कृषि पर भी प्रभाव पड़ा है। होलसेल प्राइस इण्डेक्स और कंज्यूमर्स प्राइस इण्डेक्स, यह दोनों बढ़े हैं, मगर पिछले चार महीनों में जो उसमें बढ़ोतरी हुई थी, उसमें जरूर रोक लगी है। मान्यवर, जो माननीय सदस्यों का कहना है कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव हुआ है। मैं नहीं मानता कि वर्ल्डबैंक और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की वजह से प्रभाव हुआ है। जब आपकी सपोर्ट की सरकार थी और वह जब गिर गई तो हमारे देश में के पास सिर्फ 1500 करोड़ की फारेन-एक्सचेंज था और सारी दुनियां का हमने देना था, हमारी क्रेडिट जाने की बात आई थी और उस वक्त सरकार को दुनियां में कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था। उस सरकार की क्रेडेबिलिटि भी खतम हो गई थी। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर सारी दुनियां में हिन्दुस्तान का व्यवहार करना है और अगर राष्ट्र को चलाना है तो कहीं न कहीं पैसों का बैलेन्स रखना ही होगा। जब नरसिंह राव जी की सरकार यहां आई तो इस सरकार के आने के बाद हमारे मान्यवर वित्तमंत्री जो यहां बैठे हैं, जो बहुत बड़े अर्थ-शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, इन्होंने अपनी नीति अपनाई और आज उसकी वजह से हमारे देश की एक क्रेडिट बनी दुनिया के बाजार में और जिससे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड हमें कर्जा देने के लिए आगे आए। जो उन्होंने सब क्रेडिट गंवा दिया दी थी, वह बनी है और उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारा जो बैलेन्स आफ पेमेन्ट डिस्टब होने वाला था, उसमें सुधार आया।

मान्यवर, यह जो डेफिसिट फाइनेन्स है, ट्रेड गैप है और जैसे मेरे मित्र जगेश भाई ने भी सुबह प्रश्नकाल के दौरान बात उठाई थी. यह हमें देखना है। मगर, एक बात का डर हमें जरूर है कि हमारे देश में जो सेल्फ रिलाइन्स की नीति, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी ने अपनाई थी, हमें डर है कि कहीं इस मेलजोल में या इस दुनिया के लेनदेन में हमारी वह नीति पीछे न रह जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी 80–90 करोड़ है अर्थात् जो खाने वाले मुख हैं वह 80–90 करोड़ हैं और उत्पादन हमारे देश का कम है, कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। हमारे कारखानों में भी जो उत्पादन होता है वह भी सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। इसलिए एक इकोनोमिक मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं, उसके अनुसार हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की अपनी नीति होनी चाहिए। वैसे मैं जानता हूं कि प्रयास तो काफी हो रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जरूर कमी रही है क्योंकि अगर आप देखें तो सन् 1980 से सन् 1990 तक हमारे यहां अनाज का प्रोडक्शन 130 मिलियन टन से बढ़कर 170 मिलियन टन तक बढ़ा है। तो उस दशक में अनाज का प्रोडक्शन काफी बढ़ा है और हिंदुस्तान में अनाज प्रोडक्शन की केपेसिटि बहुत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे वित्तमंत्री जी यहां बैठे हैं, इनकी मैं इसलिए भी सराहना करता हूं, गत साल वर्ल्ड बैंक के फिगर देखें, हमारे रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट देखी है उसमें हमारा नेशनल जी.डी.पी. सात लाख करोड़ रुपए तक गया है।... उसके बाद अगर आप कहीं भी जाइए, देहातों में जाइए, पहले जो लेबर हमें बहुत सस्ते में मिलती थी खेती में काम करने के लिए, अब वह मंहगी हो गई है। मतलब मनुष्य के जीवन का स्टेंडर्ड बढ़ा है और इसका इन्फ्लेशन भी एक कारण है। रुपए का अवमूल्यन हुआ, कीमतें बढ़ने के कारण जब सरकार सत्ता में आई तो रुपए का अवमूल्यन हुआ 20–25 प्रतिशत, उसके कारण भी कीमतें बढ़ गईं। मगर उसके अलावा भी क्या करना बाकी है, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में जो नई एग्रीकलचर पालिसी आ रही है, जाखड़ साहब ने कहा था कि इसी सत्र में हम रखेंगे, मगर अयोध्या और मंदिर के मसले ने सारी की सारी पालिसीज़ को पीछे रख दिया और दो सप्ताह तक हमारे यहां यही बहस होती रही कि मंदिर होगा या मस्जिद होगी। मगर मंदिर और मस्जिद के अलावा जो 70–80 प्रतिशत भूखे लोग हमारे देश में हैं, जो गरीब हैं, उनका क्या होगा? यह सोचने के बजाए हम मंदिर और मस्जिद के लिए झगड़ते रहे जो प्रभु श्री राम के सिद्धांत के बिलकुल विपरीत हैं और यह नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर पूरी तरह से उसका कड़ा विरोध किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो 451 फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें खेती होती है, उसमें से 171 जिलों में 80 प्रतिशत इरिगेशन है। हमारा जो पूरा इरिगेशन है उसमें से सिर्फ 171 डिस्ट्रिक्टस में 80 प्रतिशत इरिगेशन हैं। मतलब 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 80 प्रतिशत इरिगेशन है और उसमें से 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं which produce 50 per cent of foodgrains. तो 451 में से 51, मतलब ऐसे हो गया कि 1/9 1 तो 1/9 जो हमारा एरिया है, अभी टैकल हुआ है एग्रीकल्चर का, अगर इसी तरीके से 51 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर 50 प्रतिशत फूड प्रोडक्शन होता है, अगर 451 डिस्ट्रिक्ट्स तक हमारा यह सारा काम चलता गया तो हमारे देश का अन्न-धान्य प्रोडक्शन 765 मिलियन टन तक जा सकता है। जैसे 51 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 प्रतिकत अनाज का प्रोडक्शन हो सकता है, अगर उसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन फेसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता, अच्छे बीज और किसानों को नई टैक्नोलोजी दी गई तो इसी हालत में, इसी स्टेटस में हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 765 मिलियन टन तक जा सकता है. और

20वीं शताब्दी के अंत तक हमारी जरूरत है 210 मिलयन टन । अगर यह हो गया तो हमारा आधे से ज्यादा फूड ग्रेन डेफिशन, जो दुनिया में ऐसे देश हैं कि प्रजनके यहां अनाज नहीं है, उनको एक्सपोर्ट करने से हम एक लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपयों क. फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं और वर्ल्ड बैंक और आई. एम.एफ. को कर्ज देने की शक्ति हमारे देश में आ सकती है । इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर वित्त मंत्री जी, आप 8वीं योजना बनाने जा रहे हैं, हमने सुना है, समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है कि कृषि के लिए और ग्रामीण रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध कराने की आप बात कर रहे हैं । ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध करा कर हमारे देश की कृषि और कामगारों पर आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं । आप पर-केपिटा कितना एक्स-पेंडिचर कर रहे हैं, इस हिसाब से कीजिए, ज्योग्राफिकल एरिया लीजिए । हमारी 70 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, 70 प्रतिशत नियोजन का पैसा उन पर खर्च कीजिए तो आपका जो बैलेंस, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेन्ट है ऐसे ही बैलेंस आफ एक्स-पेंडिचर योजना में है, वह भी ठीक तरीके से जम जाएगा । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि Industry and agriculture must go hand in hand.

इंडस्ट्री पर तो बहुत खर्चा कर चुके हैं हम, मगर बात ऐसी है कि एक सेचु रेशन प्वाइंट आता है उसके पास, मगर फिर भी दो-तीन लाख छोटी-छोटी स्माल स्केल इंडस्ट्री हैं

They have become sick in the industrial sector.

अगर नए-नए कारखाने खोल रहे हैं तो उसके बजाए यह भी देखिए कि जो दो-तीन लाख पुराने छोटे-छोटे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, जो बीमार पड़े हुए हैं, उनको भी कुछ दवा-पानी दीजिए, उनको भी शुरू कीजिए और जिनका नुकसान हुआ है, उनको कुछ राहत देने का प्रयास कीजिए।

THE VICE-CHARMAN(SHRI SYED SIBTEY RAZI): We have many speakers on the list and I request the hon. Members to be a little brief.

SHRI VTHALRAO MADHAVRAOJADHAV: I will finish in two minutes.

दूसरी बात, मैं बतलाना चाहता हूं हूं कि मैं फर्टिलाईजर प्राइसेज कमेटी में था । आज फर्टिलाइजर की प्राइसेज बढ़ने से देश में बहुत हलचल मच गई । हमारी कमेटी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि प्राइसेज बढ़ाई जायें । कमेटी ने कहा है कि सब्सीडी रखी जाये, किसानों पर कोई हार्म न किया जाये । मगर जो छोटे कारखाने थे उनकी हालत बहुत खराब थी । सही बात तो यह है कि उनको सब्सीडी देनी चाहिये थी । मगर पता नहीं कि फर्टिलाइजर प्राइसेज पर डिस्कशन होने वाला था, यह मंदिर और मस्जिद में हमारे किसानों की फर्टिलाइजर की तथा और जो समस्यायें थीं, सारी रह गई । देश की सारी समस्यायें ऐसी रह गई जिनका संसद में डिस्कशन होना था । दूसरी मुख्य बात यह कहना चाहता हूं कि इरिगेशन एंड सोइल एंड वाटर मैनेजमेंट शुड बी गिविन टाप प्रायोरिटी । जैसा कि हम देखते हैं कि अभी जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, उस उपलब्ध पानी का मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से किया तो हमारे पास 60 प्रति त और 50 प्रतिशत पानी जमीन से दे सकते हैं । अगर इससे पानी का मैनेजमेंट अच्छा किया तो 100 प्रतिशत जमीन हमारे पानी के नीचे आ सकती है और यह बहुत जरूरी है उसके साथ जो पानी देते हैं तो उस जमीन में जो सिकनस आता है उसको भी रोकना बहुत जरूरी है । इसलिये सोयल एंड वाटर मैनेजमेंट, इसको भी प्राथमिकता देनी चाहिये ।

जो कीमतें कम करने की बात है, सरकार ने इधर के आंकड़े उधर डाले या कामगारों को ज्यादा पैसे दिये या वेजेज ज्यादा बढ़ा दिया या दो-चार लाइसेंस ज्यादा दिया तो

उससे कीमतें रूकने वाली नहीं है । कीमतें उस वक्त रूकेंगी जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन उसी वक्त बढ़ेगा जब हम कृषि को प्राथमिकता देंगे । कृषि को प्रथम प्रिफेंस और इंडस्ट्री को सेकेंड प्रिफेंस । ग्रामीण क्षेत्र के लिये अगर हम प्रायोरिटी देंगे, गांधी जी ने कहा था कि सही भारत ग्रामों में रहता है और वहां चर्खे की जो बात कही थी वह चर्खे की बात नहीं थी । एक ग्राम में भी एक गरीब आदमी चर्खे जैसा एक छोटा इंस्ट्रूमेंट लेकर अपना जीवन बिता सकता है । यह एक रास्ता दिखाया था । मगर हमने उसको समाप्त कर दिया और अब बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं । बड़ी इंडस्ट्री के लिये मेरे दिल में कोई अलग बात नहीं है मगर स्माल स्केल इंडस्ट्री, न्यू टैक्नालाजी वह भी ग्रामीण क्षेत्रों में जानी चाहिये, उसको भी प्राथमिकता देनी चाहिये और हमारे देश की जो आठवीं पंचवर्षीय योजना आने वाली है जिसका डिस्कशन अभी यहां नहीं हुआ, जो होना बहुत जरूरी था । मगर वह भी मस्जिद और मंदिर के झगड़े में पीछे रह गया । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं और सदन में सारे बहुत अच्छे विचारों के नेता भी बैठे हैं, तो कम से कम अगले सेशन में न्यू एग्रीकल्चर पोलिसी और आठवीं पंचवर्षीय योजना पर पहले डिस्कशन किया जाय और हमारे देश के विकास का जो मुख्य धारा है, उसको जोड़ा जाय । देश में अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें अपने आप घटेंगी और फिर एक दफे महात्मा गांधी की जो भावनायें हैं उनके लाने से मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस पर पूरी तरह ध्यान दिया जाये । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री संघ प्रिय गौतम : (उत्तर प्रदेश) : सम्मानित उपसभाध्यक्ष महोदय, अपने सदन के सम्मानित सदस्य माननीय मोहम्मद अमीन द्वारा सदन के समक्ष लाये गये इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारी वर्तमान सरकार, केन्द्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, पी०वी० नरसिंह राव की सरकार चाहे कितने ही बहाने बनाये, चाहे कितने ही कारण बताये चाहे आंकड़ों की लीपापोती करे वह इस तथ्य को नहीं छिपा सकती कि इस सरकार के आने के बाद और इस सरकार के घोषणा पत्र में दी गई घोषणा के बावजूद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है । पेट्रोलियम पदार्थों और पेट्रोलियम पदार्थों से पैदा की हुई चीजों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का प्रभाव तो सारे देश पर पड़ा है । लेकिन इसका कुप्रभाव उन लोगों पर पड़ा है जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, मजदूर हैं और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं । मान्यवर, मैं आलोचना में नहीं जाऊंगा । आलोचनाओं से सदन का सारा समय बरबाद होता है और हमारे एक माननीय सदस्य सुन जाते तो अच्छा होता । उन्होंने कहा कि राम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में ही समय बीता है मैं भी चाहता था कि यह चैप्टर क्लोज हो जाता । जब किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जान बूझकर हत्या हो जाय और हत्यारों को देख भी लें तो हत्यारे गिरफ्तार किये जाते हैं, मुकदमे चलते हैं, सजायें मिलती हैं, उनकी जमीन भी कुर्क करली जाती है, उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है या की जा सकती है । लेकिन वह व्यक्ति जिसकी हत्या हुई हुई है, वह जिन्दा नहीं हो सकता । उसे कोई जिन्दा नहीं कर सकता । भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे संगठन हैं, जिनसे संबंध बताए जाते हैं, आरोप लगाया गया कि 6 दिसम्बर को, चूंकि संदर्भ आ गया है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं मस्जिद को तोड़ दिया, मस्जिद को तोड़ दिया, बराबर यही कहा गया । सरकार ने स्वीकार कर लिया, नैतिक जिम्मेदारी ले ली, इस्तीफा दे दिया । पार्टी प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ । नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, पाबंदी लग गई संगठनों पर और सरकारें भंग कर दी गईं लेकिन जो हत्या हुई थी, इसको फिर जिंदा कर दिया कांग्रेस के लोगों ने और फिर इस मुद्दे को खड़ा कर

दिया । जब हत्या हो गई तो हो जाने देते और जो सजाएं आप दे रहे थे वह देते . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHARiMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI,: Mr. Gautam, please try to concentrate on the Resolution,

श्री संघ प्रिय गौतम : तो आपने अभी जो बात कही इसमें फिर समय नष्ट होगा इस सदन का अगर ये मुद्दा जिंदा रहा । इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सदन नहीं चलेगा जब तक यह मंदिर-मस्जिद मुद्दा रहेगा ।

इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मूल्यों में वृद्धि हुई है और क्यों होती है मूल्यों में वृद्धि ? सब जानते हैं हमारे वित्त मंत्री जी बहुत काबिल है लेकिन वित्त मंत्री जी काबिल हैं पढ़ाई लिखाई में । वित्त मंत्री जी से अगर हल चलवाया जाए तो फाला मार देंगे । यह क्या जानें खेती कैसे होती है । हर बात में अपनी जगह पर एक्सपर्ट होता है । प्रधान मंत्री बड़े अच्छे वैज्ञानिक हैं लेकिन वे क्या जानें कि ईंट कैसे बनती है । तो हमको प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि कहां से अर्थ नीति का प्रारंभ होता है, जहां से अर्थ नीति प्रारंभ होती है, उस पर हम ध्यान दें और वह है उत्पादन को बढ़ाना ।

अब खेती के उत्पादन में कमी आई । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कैसे आई ? खेती का उद्योग बीमार हुआ । कैसे हुआ ? खेती का उद्योग तब बीमार होता है जब खाद न मिले, पानी न मिले, बिजली न मिले, बीज न मिले और जो पैदा की हुई चीज है वह विदेशों में ना जाए या उसका दाम कम मिले । अगर खेती बीमार हुई है और खाद्यान्नों की कमी हुई है तो उसका कारण क्या है ? इसका जिम्मेदार कौन है ? क्या आपने किसानों को खाद दिया ? आपने खाद नहीं दिया बल्कि जो खाद मिल रहा था उस पर आपने रोक लगा दी । खाद के दाम आपने बढ़ा दिए । कौन जिम्मेदार है इसके लिए ? खेती के उत्पादन में कमी आपके कारण आई । क्या आपने पानी की व्यवस्था की और पानी की व्यवस्था को बढ़ाया ? कितनी नयी नहरें आपने खोदीं, कितने नए ट्यूबवैल आपने लगाए, कितने कुंए पानी के लिए आपने बनाए, कितने सिंचाई के साधन आपने बढ़ाए ? अगर नहीं बढ़ाए तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो आपके सामने है उसमें क्या-क्या प्रावधान किए हैं, उनको सदन के सामने प्रस्तुत किया जाए । यह सदन जानना चाहता है कि आपने क्या व्यवस्था की है ।

अगर यह नहीं होगा तो खेती का उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? खेती के उत्पादन को बढ़ाने के जिम्मेदार आप हैं । उद्योग कब बीमार होते हैं जब कच्चा माल न मिले या श्रमिकों की हड़ताल हो जाए । श्रमिकों की हड़ताल नहीं हुई और कच्चा माल भी मिला, फिर भी उद्योग का उत्पादन गिरा । मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे देश से हम तथाकथित समाजवादी देशों को साईकिल भेज रहे थे और बड़ी मात्रा में जूते भेज रहे थे । हमारे देश के जूतों का व्यापार विदेशों में बंद हो गया । वह इसलिए बंद नहीं हुआ कि जूतों के लिए कच्चा माल नहीं मिला या श्रमिकों की हड़ताल हुई बल्कि इसलिए कि जूतों की क्वालिटी को गिराया गया । जूतों की क्वालिटी को गिराया गया, साईकिलों की क्वालिटी को गिराया गया और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपनी चीजें बेचकर मुद्रा नहीं कमा सके । इसके लिए जिम्मेदार लोगों को क्या आपने सजा दी ? क्या उनको आइडेंटिफाइ किया ? क्या आपने उनके लाइसेंस रद्द किए और जो लोग जूते बनाते हैं क्या आपने उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर यह काम उनको दिया ? यह नहीं दिया । मुझे मालूम है आगरा में शैड्यूल्ड कास्ट की एक कौम है जो बढ़िया जूते बनाते हैं और जिन पर बाटा की मुहर लगती है । लेकिन वह नहीं भेज सकते हैं । आपकी एस०टी०सी० और आपके दलाल उस माल को बाहर भेज सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसके जिम्मेदार आप हैं ।

दूसरे, आपने खेती के लिए ऐग्रि-कल्चरल प्राइस कमीशन बैठाया जो खेती के दाम तय करते हैं। लेकिन आपने कभी उद्योग प्राइसेज़ कमीशन बैठाया? आपने उद्योगों में पैदा की गई चीजों के दाम निर्धारित किए? साबुन कितने का बिकना चाहिए, आपने कभी तय किया? ... (समय की घंटी)

मान्यवर, मैं तीन चार सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अभी यहां पर सरकार को कोसा जाता है कि जनता दल सरकार की नीति से यह हुआ। ढाई तीन साल में केवल एक सरकार आई नहीं तो आज़ादी के बाद से इस देश की सरकार आपकी रही है। आज़ादी को छोड़ दीजिए, जिस दिन से संविधान लागू हुआ और चुनाव हुए 1952 से लेकर 1992 तक 40 साल में साढ़े तीन साल दूसरों की रही बाकी आपकी सरकार रही है। तीन चार साल भी जिनकी सरकार रही है वह भी आपमें से निकले हुए लोग थे चाहे वह मोरारजी देसाई हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों। हमारे यहां एक किस्सा है –

जैसी जाकी माई, तैसी ताकी जाई।
नानी की छवि धेवती में आई।

तो जैसे कांग्रेसी वैसे कांग्रेस से निकले हुए भाई। तो सारी सरकारें कांग्रेस की ही रहीं। नीतियां आपकी रहीं। नियम आपके रहे तो परिवर्तन आता कहां से? लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो एफ०सी०आई० के गोदामों में गेहूं सड़ रहा था, मजदूर भूखे मर रहे थे। उस समय सरकार ने एक योजना बनाई कि हर गांव को कच्ची सड़क से जोड़ दो और काम के बदले अनाज दो। मजदूरों को भूखा मरने नहीं दिया और गोदामों में अनाज को सड़ने नहीं दिया। साम्यवादी भाइयों की मैं तारीफ करता हूं कि सबसे ज्यादा बंगाल की सरकार ने उस स्कीम को लागू किया। आप तो सच बात कहते नहीं हो, हमेशा इनकी (कांग्रेस) की मदद करते हो, लेकिन मैं सच्ची बात करता हूं। तो बंगाल की सरकार ने उसका सदुपयोग किया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, खर्च कम हो, खपत कम हो, डिमांड कम हो, इसके लिए क्या उपाय आपने किए हैं?

आप कहते हैं कि जनसंख्या पर रोक लगा दो। जब भी रेडियो या टेलिविज़न खोलते हैं, समाचार आते हैं तो यही कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या क्यों बढ़ रहे हो इसके लिए आपने कोई उपाय किए? आपने कह दिया कि दो बच्चे से ज्यादा होंगे तो टिकट नहीं देंगे। क्या यह नहीं कर सकते थे कि उत्तराधिकार का अधिकार और सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे। आप जनसंख्या को कम करना चाहते हैं लेकिन चोर से कह रहे हो चोरी करो और शाह से कह रहे हो माल रखाओ। दोहरी नीति आपकी हो रही है और आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। आपका खर्चा ज्यादा फिजूल-खर्ची में है। मैंने एक सवाल उठाया था कि यह शताब्दी ऐक्सप्रेस कानपुर से चलती है, 5 बजे नाश्ता मिलता है, नाश्ते में दो समोसे मिलते हैं, मिठाई मिलती है, रसगुल्ला मिलता है, बिस्कुट मिलते हैं, उसको दो घंटे बाद खाना मिलता है। आधा खाना वेस्ट जाता है। क्षमा करेंगे मेरे माननीय सदस्य सेन्ट्रल हाल में बैठकर जब खाना खाते हैं, तो आधी चीज प्लेटों में ही छोड़ देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रिज़े) कृपया समाप्त करने की कोशिश करें।

اپ سبھا ادھیکش (شری سید سبط رضی): کرپیا سماپت کرنے کی کوشش کریں۔

श्री संघप्रिय गौतम : होटलों में खाना खाते हैं तो आधा खाना प्लेटों में छोड़ देते हैं। यह फेंक दिया जाता है। ऐसा बचा हुआ खाना भूखे गरीब लोगों के काम आ सकता है जिनको खाना नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था: जय जवान जय किसान। क्या कांग्रेसी भाई मतलब समझे थे उसका ....

उपसभाध्यक्ष श्री सैयद सिब्ते रज़ी) : कृपया समाप्त करने की कौशिश करें ।

اپ سبھاادھیکش: کرپیا سماپت کرنے کی کوشش کریں۔

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं खत्म कर रहा हूं। आई नैवर टाक इररिलेवेंटरी । फिर भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये कम्युनिष्ट भाई भी वह बात नहीं कहते जो मैं कहता हूं । (व्यवधान) मुझे शिकायत आपसे है कि आप इनका साथ देते हैं । (व्यवधान) जय जवान जय किसान कहा था तो किसान से क्या मतलब था । छत पर गेहूं उगवाइये। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था किचन गार्डन में गेहूं उगवाइये । यह सो एकड़ की जमीन शांति वन विजय घाट शक्ति स्थल के लिए क्यों छोड़ दी गई है । 10 मीटरमें उनकी समाधि बना दीजिए बाकी सारी जमीन में खेती करवाइये। किस लिए छोड़ी गई है यह जमीन । लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था हफ्ते में एक दिन का खाना छोड़ना चाहिए । आप आज कहिए कि हम हफ्ते में एक दिन का खाना छोड़ देंगे इसके अलावा तीन बातें जो मुहम्मद अमी जी ने कही मैं उनके बारे में बताना चाहता था किन्तु घंटी बज रही है। मेरे पास अमूल्य सुझाव हैं, विश्लेषण है लेकिन कभी समय आने पर बताऊंगा आज मैं केवल-दो-ती सुझाव दो मिनट में रखकर खत्म करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी) कृपया मेहरबानी करें।

اپ سبھاادھیکش: کرپیا مہربانی کریں۔

श्री संघ प्रिय गौतम: सरकार की गलत नीतियां हैं । आप कहते हैं गलत नीति नहीं हैं । आप स्वीकार नहीं करते । अभी आप भाषण दे देते हैं कि गलत नीति नहीं है। कह दीजिए थोड़े दिन के लिए बड़े उद्योग केवल वही इस देश में रहेंगे जो यहां देश के पैदा किये हुए माल को विदेशों में भेजेंगे और विदेशी मुद्रा कमाकर लायेंगे । बाकी ऐसे घरेलू उद्योग कुटीर उद्योग, एग्रो बेस्ट और छोटे उद्योग मझोले उद्योग ही यहां एस्टाबलिश कीजिए जिससे लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। स्व-रोजगार योजना आप यहां पर फलीभूत होने दीजिए। पैदावार बढ़ाने के लिए बजाय इसका प्राइवेटाइजेशन करें, फेक्ट्रियां बंद करें, इनके कारणों में जाइये कि ये बीमार क्यों होती हैं । मैं आपको बता दूंगा क्यों बीमार होती हैं । मेनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन आप उन लोगों को भेजिए जो यह जिम्मेदारी लें कि हम इस उद्योग को जिंद कर देंगे । आप उनसे कमीशन लेकर चुनाव में रकम तय करके नियुक्ति मत कीजिए बहुत से लोग हैं जो इस बात के लिए आगे आयेंगे ।

उपसभाध्यक्ष श्री सैयद सिब्ते रज़ी : आप कृपया खत्म करिये) ।

اپ سبھاادھیکش "شری سید سبط رضی": آپ کرپیا ختم کرئیے۔

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं डिस्पिलिंड आदमी हूं और मेरी पार्टी भी । इसलिए मैं आगे न कह कर केवल इतना कहना चाहता हूं । (व्यवधान) इन साम्यवादियों की तरह और मैं आपकी तरह इनडिसस्पलिंड नहीं हूं। तुम तो मन्दिर मस्जिद चिल्लाते रहते हो । तुम्हारा मस्जिद में क्या मतलब, तुम्हारा धर्म से क्या मतलब है। मार्क्स ने कहा था --अफीमची धर्म अफीम की गोली है तुम क्यों धर्म की बात करते हो । ढोंगी आदमी जो हो। मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा हूं आप अगर इजाजत दें और सदन चाहे तो मैंने थोडा सा गांव में रहकर जो काम किया है। बताना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी) : फिर किसी समय पर और किसी विषय पर अपने मूल्य विचार दें। आपके बहुत अमूल्य विचार हैं । अभी समय बहुत कम है।

اپ سبھاادھیکش: پھر کسی سمے پر اور کسی وشے پر اپنے مولیہ وچار دیں۔ آپ کے بہت امولیہ وچار ہیں۔ ابھی سمے بہت کم ہے۔

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे बुलन्दशहर में एक शुगर मिल थी । सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ढाह दिया । कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस का राज था । एक करोड़ रुपये का

का घाटा हो गया मिल में । मिल बंदद होने लगी । किसानों का गन्ना खराब होने लगा । एक अफसर ने कहा मुझे जनरल मैनेजर बनया दीजिए मैं लाभ दे दूंगा । तीन महीने के लिए वह व्यक्ति जनरल मैनेजर बना दिया गया । स्वर्गीय राजनारायण जी के विश्वासपात्र थे और बाद में उनके स्पेशल एसिस्टेण्टस भी रहे । उन्होंने तीन महीने के अन्दर 34 लाख रुपये का फायदा दिया और रिकवरी 7 परसेंट के बजाय 8 परसेंट कर दी । लेकिन कमीशन कांग्रेस के लोगों को नहीं दिया । इसलिए तीन महीने के बाद उनको हटा दिया गया । आप अपने गिरेबान में हाथ डाल कर देखिये कि बीमारी कहां है . . . (व्यवधान) । मद डालकर देखिये और साम्यवादियों आप भी देखिये कि इनका साथ क्यों दे रहे हैं ।

मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि आपकी नीति गलत है, आपकी नीतियां गलत हैं, आपके कार्यक्रम गलत हैं । आप यहां पर जो असली मुद्दे हैं उनको लाइये । आठवीं पंचवर्षीय योजना कीपुनर्विचना कीजिये, रिव्यू कीजिये और पैसे को इधर उधर करके खेती के लिए पैसा दीजिए । छोटे उद्योगों में पैसा बढ़ाइये । नई नहरें खोदिये । पानी के साधन लगवाइये । किसानों को खाद उपलब्ध कराइये । इसी तरह से जो उद्योग बीमार हैं उनके लिए ज्यादा पैसा दे करके उन्हें खड़ा कीजिए । सप्लाई और आपूर्ति को सही बनाइये । आबादी पर रोक लगाइये । जखीरेखोरों के खिलाफ एक्शन लीजिए । इन सुझावों के साथ मैं श्री मोहम्मद अमीन साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन यह कह कर करना चाहता हूं कि आप अमीन हैं, अमानत में खयानत नहीं करेंगे और इनका कांग्रेस साथ नहीं देंगे, धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Shri Suresh Pachouri. Not present.

Shri Ashis Sen. Not present.

Shri Satya Prakash Malaviya. Not present.

Shri P. T. Kiruttinan.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I am very much thankful to Mr. Mohammed Amin for having moved this Resolution saying:

"This House expresses its deep concern over the continuous rise in prices of all commodities in the country putting the common man in great distress and also over the addition to the inflationary spiral through issue of ad-ministrative orders, the latest example of which being the hike in the prices of petroleum products, and urges upon Government to take immediate comprehensive steps to arrest the, continuing rise due to the economic policies administered price hike and import of consumer items at the behest of the World Bank."

I support the Resolution, but what is the use of it. The Government may take note of it, bat nothing concrete will be done by this Government. The people of this country expect something good for them from the Government as well as from Parliament, but their expectations are belied, and the hopes and trusts of the common people, particularly those who are living in remote villages, are shattered. Sir, my personal feeling is that the Government may not be able do good things to public, but no elected government which got the mandate of the people, has he right to unleash bad and worse things on the people

In Parliament nowadays it is true that we are discussng about corruptions and malpractices. We are discussing about pay-offs inside and outside the country. We are discussing about dest ruction., and demolitions. We are dis cussing about commissions and omissions. But we have failed to discussabout projects- and pro grammes. We have failed to discuss about the ways and means to help un employed graduates and other unemployed youth. We have failed to discuss about the way-out for the millions who de pend on their barren lands and live in huts. Today we are discussing about the rise in prices of all commodities beyond the reach of the common man, putting him in great distress and also about the addition to the inflationain spiral. This is nothing but but searching for water after putting fuel into the flame. We can take this

opportunity to attack the ruling party, but what will be the result of it? Is the Government going to reduce the prices as they have promised in their election manifesto? Is the Government going to stop its misdeeds? Will this Government put off the flame or add some more oil to the flame It is evident that the policies pursued by the present Government will add more fuel to the flame. The Government is talk ing too much about the new economic policies. They are playing with the words; liberalisation, globalisation and structural adjustments. This Government has lost three D's—discipline, decorum and decency—but has acquired other three D's called devaluation, decontrol and decentralisation. The year 1991-92 is supposed to be a landmark period in terms of understanding and undertaking string policy measures for quick economic stabilisation, I want to stress that actually this policy of the Goverment only has led to the inflationary trends and sky-rocketing price rise. The increase in the general index of wholesale prices on a point-to-point basis was 9.1 per cent in 1989-90 and 12.1 per cent in 1990-91. It further rose to 13.6 per cent in 1991-92. The official wholesale price index for all commodities, basing 1981-82 at 100 stood at 229.4 in the month of September 1992. The prices of primary articles recorded the largest increase of 17.1 per cent in the year 1991-92 as against 15.3 per cent in 1990-91. The increase in the price index of food articles was of the order of 20.9 per cent as against the increase of 18.9 per cent in 1990-91. The annual rate of inflation was around 7 to 8 per cent till October 1990. It gradually speaked at 16.7 per cent in August 1991. The downward journey thereafter began, according to the Government report. The Index after reaching a low of 7.4 per cent by the week ending 12th September, 1992. resumed its upwar march in the subsequent weeks. The inflation again entered the double digit zone. According to the Government report available, it shows the annual rate of inflation has declined to 8 8 per cent by the week ending 14th November, 1992. According to the Planning Commission, they have projected the inflation rate in 1992-93 at 10 per cent. Sir, what are the causes for the current record of inflation and price spiral? According to the Economic Survey, 1991-92. Government of India. Ministry of Finance, "excess demand" is found to be the more important cause. Along with demand pull factors, supply factors have also played their role. It is a fact that the supply factors determine the pattern of relative price changes, as overall excess demand puts the greatest pressure on prices. At the start of the current inflationary phase. the prices of fuel and lubricants as well as the primary goods jumped sharply. Why, Sir? The index of the 'fuel group rose significantly because of the hikes in the administered prices of its subgroups viz- coal--24.7 per cent; mineral cils—9,2 per cent; electricity—13.7 per cent; fertilisers—28.8 per cent: cement—17.4 per cent; and non-ferrous metals--9.7 per cent. Therefore, the hikes in the administrered prices imparted considerable upward push to prices of the manufactured products group. As a re. suit this group contributed the most to the rise in the general price level in 1991-92 to 52.6 per cent as against 43 per -ent in 1990-91. It is the Government which has increased the administrered prices of all these primary goods. While you 30 and ask for votes and for capturing the power you promise to roil down the prices but after coining to power, your promises go to the dust-bin and the administered prices are increased.

The Government has got powers to fix the prices of primary goods with a view to maintain the overall price levels within the common man's reach. But the Government has misused this power and increased the administered prices which led to the inflationary trend and price spiral.

Large deviation from the safe limits of deficit financing indicated in the Sixth and the Seventh Plans created liquidity hanging over which exacerbated the demand to the full.

The difficult balance of payments position and low level of foreign exchange reserves stood in the way of arranging essential imports to augment their do-piestic availability. Therefore, supply management cannot be geared to meet a part of excess demand which has been generated by the expansionary fiscal policies of the Government and monetisa-tion of budget deficits year after year.

Expansion of money supply by 18 per cent was out of alignemnt with the real growth of less than 2 per cent in 1991-92.

Cost-push factors also explain a part of rise in prices of manufactured products. All inputs including labour are becoming costlier pushing up the prices of final products. Exchange rate adjustments in early 1991 increased the prices of imported machinery and raw materials leading to cost escalation in import incentive industries.

Sir, we. are having the Essential Commodities Act. The words "price rise" would not be in the Indian dictionaries if the Essential Commodities Act had been implemented the way it should be implemented.

Obviously the implementation of the Act has not been effective enough. The commodities declared by the Government as essential commodities include not only wheat rice, clothing etc., but home appliances, cement, soaps, jute garments, silk garments, match boxes, electric bulbs, cycle tyres and tubes, scooter and auto-rickshaw tyres and tubes, soda ash, dry cells, tractors, crude oil, threads of all varieties, coir, books, pesticides, tea, spinning equipments and powerlooms and their spare parts, non-ferrous metals, organic heavy chemicals, inorganic heavy chemicals, cinema films, cinema carbons, machines for making embroideries and laces, cloth printing machines, synthetic rubber, rayon, carbon black, PVC, polythene, polysterene, etc. etc.

This only shows that most of the goods or their raw materials which are used in our daily life form essential commodities within the meaning of the Act, production, distribution, supply and pricing of which are liable to the Govermntnt control but are not controlled.

Above all the present increase of petroleum product prices has been oije of the steepest in the recent times. In the case of HSD the increase is around 22 per cent; kerosene for industrial purposes, 32 per cent; naphtha, 36 per cent; LPG domestic, 24 per cent; LPG non-domestic, from 67 to 104 per cent; paraffin wax, 6 per cent; ATF for domestic Airlines, 10 per cent; furnace oil for fertilizers, 54 per cent. Furance Oil for non-fertilisers—25 per cent; Low Stock Heavy Sulphur for fertilisers—54 per cent; and for non-fertilisers— 26 per cent! Raw Petroleum Cake (RPC) and CPC have wvureased by 67 per cent and 37 per cent respectively. The direct impact of oil price hike on inflation works out to 1.5 per cent to 2.0 per cent in each of the last two years.

The indirect cascading effect particularly in the transport sector in the form of higher tariffs and costs was more general and widespread. The transport sector will have to bear an additional expenditure of over Rs. 400 crores and this will be passed on to the common; people by bus-fare hike. Road transports account for nearly 78 per cent of passenger traffic whch is increasing by 3.1 per cent per annum.

The goods transport sector which accounts for over 50 per cent of the goods traffic movement in the country likely to pass the burden to the consumer. The diesel price hike has put an additional burden of Rs. 96 crores on the Indian 'Railways during October to March 1993 and its impact for the full year would be around Rs. 192 crores. The total burden of recent decisions including diesel price hike, concessional freight for fertilisers and sharp rise in steel prices due to steel decontrol will be around Rs. 700 crores for the whole year. This has not been provided for in the budget for the year 1992-93 for Railways. This is going to have an effect in the coming year,

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) in the Chair]

Automobile manufacturers apprehend the latest fuel price hike would throw the industry into yet another bout of recession, reduce profit margine further and lead to a major shake-up in the market share of different manufacturers.

Naphtha and fuel oil based urea and nitrogen-based complex fertilisers manufacturers are also hit by the price-hike. Naphtha price for fertiliser industry have gone up by Rs. 1050 per tonne whereas fuel oil prices have gone up by Rs. 1122 per tonne. Since the Government has decontrolled the fertiliser prices, these increases have been simply passed on to the farmers.

According to the FICCI. "Increase in prices of diesel by 20 per cent would have cascading effect and would result in a rise in the price index". The ASSOCHAM have declared that "The price rise in pet roleum products would have far-reaching implications with industry being among the worst-hit sectors." The PHDCCl has said that "The steep price hike would seriously affect the international competi tiveness of industry. It would intensify the recessionary conditions faced by the industries besides raising general price level.

Mr. J. D. Agarwal, the Director of the Indian Institute of Finance criticised the hikes and called them "irrational". The increase would boost the unproductive inflation by 2 per cent and this inflation was animplicit tax on essential and non-essen-Ha) items which everybody including the "poorest of the poor" required.

The hike of the petroleum products prices was only in keeping with India's promise to the internaional funding agencies like the World Bank and the IMF.

Another reason for increasing the prices of petroleum products is the Government's promise to the Asian Development Bank (ADB) that the domestic prices will be linked to movement in international prices. It is true that the international prices of ᶜrude and petroleum products have increased. If this formula is accepted, why did the Government fail to reduce the price when there was down-trend in the 80s? The hike not only reflected the mismanagement of the economy by the Congress (I) Government but its eagerness to bend before the IMF and the World Bank. The plea of the Government to increase the petroleum prices is that the Oil Pool Account is heading for a huge deficit of Rs. 5000 crores. It is fact that this has created heavy outstandings to the oil production and refining companies. The Oil Coordination Committee which manages the Oil Pool Account has to pay huge dues to these companies, especially the ONGC and the IOC. As a result of the delayed payments most of these enterprises have been facing a severe liquidity crunch. Therefore, the Government has managed to starve off a sharp increase in the Oil Pool Account deficit during the current financial year by raising prices of petroleum products by 15 to 18 per cent.

This is only half of the story. The untold part about the surpluses in the Oil Pool Account are taken by the government to bridge the budget deficit. The repeated plea of the Petroleum Ministry to return the funds has been falling on deaf ears

Not only that the Ministry of petroleum and Natural Gas has earlier sought the interventions of the cabinet committee on infrastructure for immediate release of funds totalling Rs. 8200 crores of the oil coordination committee and the ONGC held up by the Ministry of Finance.

Further the Ministry of Finance is also reported to have been demanded allocation of a whopping Rs. 16411.27 crore mopped up as oil development cess over the last 17 years. This fund was to be used only for the development of oil industry.

Furthermore, an amount of Rs. 7400 crore which is lying in the public deposit is not. available to the oil sector. It is said out of this Rs. 7400 crore only an amount of Rs. 2300 crore had been transferred to the Revenue Account of the Centra] Budget four years ago by

the Finance Ministry. The Government has sanctioned a sum of Rs. 15300 crore for import of Petroleum products in 1992-93 but the demand outstripped the supply. But the domestic production has been stagnating and this is not likely to increase substantially in the near future. The amount sanctioned for import will also most probably be exhausted by December, 1992 (which means! there would be no funds for the last three months i.e., January to March.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mrs. Kiruttinan, please conclude. So many speakers are there.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTT-NAN: If you go through all these things you will find that the Government need not go in for increase in the prices of petroleum products. The Government is the culprit for all these bad things in this country. So I condemn this Government and support the Resolution brought forward by Shri Mohammed Amin.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri S. S. Surjewala. Please make a short and pointed speech because everybody wants to speak on this subject.

श्री एस. एस. सूरजेवाला : (हरियाणा) : वाईस चेयरमैन साहब, मैं श्री मोहम्मद अमीन साहब के प्रस्ताव में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने से बाकी जरूरियात, जिंदगी की चीजों पर जो असर पड़ता है महंगाई का, उस पर इतनी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन जो है और इससे ट्रैक्टर्ज हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी है, इन सारी चीजों, जिसमें भी डीज़ल, पेट्रोल और दूसरी पेट्रोलियम प्राडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, वह हर चीज की कीमत बढ़ने से उन पर असर पड़ता है।

लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो एक वायदा पिछली पार्लियामेंट के चुनाव में, श्री राजीव गांधी जी जब जिंदा थे, कांग्रेस ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में किया था कि वह जिंदगी की जरूरियात, चीजों की कीमतों में कमी करेगी। उसका एक बहुत ही मार्कंड असर आप देख सकते हैं। अगर मैं चर्चा करूं, आज लोहा जो है, सीमेंट, तेल, एडिबल आयल और अनाज, महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट पिछले दिनों में आई है, तो यह कोई गलती नहीं होगी।

लोहे की कीमतें बारह-तेरह सौ रुपए क्विंटल से घट कर आज एक हजार रुपए क्विंटल और उससे भी कम चली गई हैं। सीमेंट के एक बैग की कीमत, जिसमें 50 किलोग्राम होता है, आज वह 120 रुपए से घट कर 90 रुपए में बैग आम मार्केट में पूर्ण रूप से उपलब्ध है।

इसी तरह से एडिबल आयल जो हैं, उनकी कीमतों में भारी गिरावट पिछले दिनों में आई है। और अनाज की कीमत में भी गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर गेहूं की कीमत जो चार सौ रुपए क्विंटल, पौने चार सौ रुपए क्विंटल दिल्ली और दूसरे जो मट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं उनमें थी, आज वह गेहूं 310, 315, 320 और 325 रुपए क्विंटल पर उपलब्ध है। काटन है कपास की कीमत में पिछले साल 1500 रुपए क्विंटल काटन की प्राइस थी, उपसभाध्यक्ष महोदय, इस समय काटन की प्राइस मार्केट में एक हजार और नौ सौ रुपए क्विंटल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि किसान कपास, गेहूं और दूसरे जो अनाज पैदा करता है जो डीज़ल से अपना ट्रेक्टर अपनी और फार्म मशीनरी खास तौर से पंप सैट्स हैं वह चलाता है उसके बिजली के दर भी इन दिनों बढ़े हैं। न केवल पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के और उसके साथ खाद की कीमतें भी बढ़ी हैं। जैसे डी. ए.पी. के एक कट्टे की कीमत पिछले साल 234 रुपए थी और आज वह 355 रुपए 350 रुपए है। इस प्रकार से मैं आपका ध्यान और आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि आज इस बात की जरूरत है हम स्वागत करते हैं लोहे की, सीमेंट की और खाद्यान्न जो तेल हैं उनकी कीमतों में गिरावट को

लेकिन अनाज की कीमत में गिरावट है उसके मुकाबले में अनाज जिन चीजों से पैदा होता है, जो चीजें अनाज को पैदा करने के लिए जरूरी है, खाद, बीज, कीड़े मार दवाई और दूसरी जो फार्म मशीनरी है, जो डीजल है उसकी कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है और उससे पूरे देश के किसानों में बहुत भारी बैचैनी है। सरकार ने बजाय इसके कि वह यहां किसान के गेहूं को जो नार्थ इंडिया के पंजाब और हरियाणा और दूसरे प्रांतों में बहुमात्रा में मौजूद है और कितना ही मार्केट से आप खरीद सकते थे, बाहर से गेहूं को इंपोर्ट किया 500 रुपए क्विंटल और 550 रुपए क्विंटल से और यहां के किसान को 350 रुपए क्विंटल भी सरकार ने भाव नहीं दिया। इन सारे कारणों से किसानों में बेचैनी है। आज किसान की कपास 1500 रुपए से गिरकर एक हजार और नौ सौ रुपए क्विंटल बिक रही है। मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दूसरे और साउथ की मंडियों में भी डिस्ट्रेस सेल जो है वह कपास की, काटन की गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे इलाकों में हुई है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह बात कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट, आज ही एक सवाल के जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि एक्सपोर्ट हमारा घटा है और उससे फारेन एक्सचेंज में 1992-93 में कमी आई है। ...(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान) : महोदय, काटन का तो इंपोर्ट भी किया है।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : मैं यह कहना चाहूंगा कि काटन को एक्सपोर्ट करना चाहिए और सरकार बहुत सा फारेन एक्सचेंज कमा सकती है काटन को एक्सपोर्ट करके और गेहूं को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसान की मदद करनी चाहिए। खाद के दाम घटाने चाहिएं और डीजल के दाम बढने से, पैट्रोलियम प्रोडक्टस के दाम बढ़ने से, बिजली के दाम बढने से जो किसान को हानि हुई है जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले सालों में अनाज की, गेहू की और दूसरी चीजों की पैदावार में कमी आए, डाइवर्सीफिकेशन हो और मुल्क को बड़ा भारी नुकसान हो करोड़ों-अरबों रुपए फारेन एक्सचेंज में आपको फिर दोबारा से अनाज मंगवानी के लिए खर्च करने पड़ें। इस बात में सरकार बुद्धिमानी दिखाएगी और इस वक्त किसानों की सहायता करेगी। और किसान की जो जिंस हैं उनको एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट नहीं करेगी और उसका जो नुकसान खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा अभी हमारी गेहूं की कीमतों जो हैं वह शायद इसी हफ्ते में आज कल में सरकार एलान करने वाली है। जो प्रचेज प्राइस है व्हीट की और मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि कम से कम 50 रुपए 60 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से गेहूं की कीमतों सरकार को बढ़ानी चाहिएं ताकि किसान को जो घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, उस कमी को पूरा किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं, आपक धन्यवाद करता हूं।

SHRIMATI ILA PANDA (Orissa); Mr. Vice-Chairman, Sir, it is now well-kown throughout the world about India's gigantic efforts to deregulate and liberalise its economy with the long-term objective of not only catching up, but, surpassing the phenomenal growth achieved by certain other developing countries, Market economy is the word of the day throughout the world, till recently among the East European nations and in the former Soviet bloc of countries. Therefore, India's efforts to achieve these broad goals are not only encouraged by the developed countries, ubt are being keenly watched for their implementation. My objective is only to highlight in a limited way the plight of the common man when the national objective is undergoing a fundamental structural change, It is an accepted fact that to achieve market economy as quickly as possible, all subsidies, direct or indirect, have to cease. India's eco-political ethos, however, will undoubtedly exert resistance to these structural changes. Reduction in fertilizer subsidy and sudden upward revision of administered prices in essential petroleum products have only en-

hanced this resistance. As a result, the rise in costs of the transporters, manufac turers and farm producers is being passed on to the helpless consumers whose only theoretical consolation is the well-adver tised reduction in inflation rate promising price stability in the future. But, in reality, the consumer, at present, is reel ing under a double squeeze of damand-pull and cost-push effects of inflation. Although the Government claims credit for reducing the point-to-point inflation rate from a high of 17 per cent last year to a low of nearly 7.4 per cent this year and it has, in fact, taken advantage of this situation by steeply increasing the administered prices, the, more relevant ag gregate inflation for the year has hardly undergone any change which is still hover. *ing around 12 per cent and 13 per cent.* Presently, I am prepared to lend my sup port to the total deregulation, market econ omy and the full convertibility of rupee on condition that the Government clearly proves its capacity to manage the finan cial and other discipline, including cont rol on broad money supply, whether due to increase in foreign exchange assets or RBI credit to Government, and takes proper and adequate measure to contain the demand-pull and the cost-push effect so. that the common man is not ruined in the meantime. It has been proved by many countries, including some of the developing ones, that such planning and implementation are feasible with minimum inconvenience to the consu mer. Providing subsidies has been the main national pre-occupation in our country for decades. It is high time under the new economic policy. Govern ment should ensure that all subsidies, direct or indirect, provided to the manu facturing or farm sector should be to tally passed on to the consumer. In addition, Government should also ensure that the manufacturers and farmers should absorb substantial part of their cost escalations due to the increase in admi-nistered prices by high productivity. In a country as large as India, many anomalies do crop up between the intention and implementation of certain policies. My intention is not to Pick up all these anomalies and highlight them in this august House. I would, however, point out a specific instance which can directly affect the common man. In this context, one may ask; Should price behave after the rise in procurement price of rice? As of now, the procurement price is higher than the wholesale price for certain varieties of rice. There is no good raeson why traders should sell rice at a price lower than the statutory price,

The long-term objective of containing inflation within single digit is only a step in the right direction. The ideal situation would be one which accelerates growth and reduces inflation to 3 or 4 per cent. Therefore, the direction *of macro- economic management should be to* correct the basic imbalances and to modernise the economy with techno-logi-.'a'ly innovative and entiepreneurial leadership. If the Government can-take UP THE challenge of putting the economy on high-growth low-inflation path through economic reform and strategic liberalisation, it would receive support from every one. I have to only caution, any failure on the part of the Government, while implementing the *economic* liberalisation, could have disastrous effects on the whole nation. In the end, I support the Bill and demand that the Government should take strong steps. Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल निर्विवाद है कि आज इस देश में जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनकी कीमतें लगातार बढ रही हैं और इस पर नियंत्रण करने में या इस पर रोक लगाने में यह सरकार पूरे तरीके से असफल रही है । जब ऐसी हालत है तो मेरे विद्वान मित्र श्री मोहम्मद अमीन ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, इसके प्रत्येक शब्द से और उसकी जो भावना है उससे मैं पूरे तरीके से सहमत हूं और उसका समर्थन करने के लिए मैं खडा हुआ हूं । इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले साल, सवा साल, डेढ साल के अंदर आम आदमी का इस देश में जीना दूभर हो गया है । मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री राजेश्वर ठाकुर को भी इस बात से

सहमत होना पड़ेगा, भले ही उनकी सरकार की जो नीति है उसके चलने ही या जो आर्थिक सुधार का दावा किया गया है उसके चलते ही इस देश में महंगाई बढ़ी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे रखूं, मैं, जिस पार्टी की आज सरकार है, उसके चुनाव घोषणा-पत्र आम चुनाव, 1991 के कुछ उदाहरणों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह चुनाव घोषणा पत्र है, – आम चुनाव, 1991 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का । इसके पृष्ठ 9 में कहा गया था– "आर्थिक तबाही में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की फिजूलखर्ची ने हमारा खजाना खाली कर दिया है । कीमतें आसमान छूने लगी हैं । मुद्रास्फिति की दर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष से भी ज्यादा हो चुकी है । खाना, कपड़ा, मकान और यातायात सभी कुछ और महंगे हो गए हैं । मार्च, 1990 के बजट ने गरीबों मध्यवर्गीय लोगों को और भी तबाह कर दिया है। रेल भाड़े, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से जरूरत की चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है । अक्टूबर, 1990 में ईंधन की कीमत में वृद्धि की मार भी करारी रही । आर्थिक विकास धीमा हो गया है । पूंजी-निवेश घटा है । बेरोजगारी बढ़ी है । आम आदमी को पूरी तरह दरिद्र बना दिया गया है । देश आज भारी वित्तीय घाटे के नीचे दबा है । भुगतान का संतुलन बटा है । हमारे निर्यात थम रहे हैं, आयात पर कोई काबू नहीं रहा । पूंजीगत खाता घोर संकट में है । विश्व बाजार में हमारी साख इतनी कभी नहीं गिरी थी । अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति में हमारा मखौल उड़ाया जा रहा है ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह बात, जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में हैं, अक्षरशः कांग्रेस पार्टी की आज की सरकार पर लागू हो रही है क्योंकि भारत सरकार के मंत्री या वित्तमंत्री भिखारी की तरह कटोरा लेकर के विदेशों में कर्ज लेने के लिए गए और यहां दुर्भाग्य की बात है कि पिछली बार जब पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बा... गई और यह वृद्धि की गई जिस रात इस देश के विदेश मंत्री डा. मनमोहन सिंह विदेश के लिए, गए ठीक उस दिन सुबह लोगों को जानकारी हुई कि कल रात डीजल, पैट्रोल और खाना पकाने की गैस, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है । यह इस बात को साबित करता है कि आज की भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जो हैं उसके दबाव में बनाई जा रही है । इसके चलते जो उरवक है, उसकी रियायत समाप्त की गई, उसकी सबसिडी को समाप्त किया गया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने चुनाव घोषणा- पत्र में कुछ वादा भी किया था और वादा यही नहीं किया था कि सस्ती करेंगे, सस्ताई लायेंगे, महंगाई को कम करेंगे बल्कि यह कहा था कि कुछ चीजों की कीमतें, जुलाई, 1990 की जो कीमतें थी उन दरों पर वापस ले जाएंगे ।

उनके चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ 24 में कहा गया है :—

"कांग्रेस डीजल, मिट्टी के तेल, खाने के तेल नमक, साइकिल तथा दुपहिया वाहनों, बिजली के बल्ब, सूती साड़िया, साधारण पहनने वाली धोती, स्टोव, बगैर धुएं के चूल्हें, छपाई के कागज, पोस्ट-कार्ड, अंतर्देशीय पत्र तथा लिफाफे, के दामों को जुलाई, 1990 के दामों पर वापिस ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं ।"

इस बात को मई, 1991 में कहा गया था, सात-सवा साल पहले की ये चीजें जिन कीमतों पर थी, उन्हीं पर हम उनको ले आयेंगे । लेकिन अपना वायदा तो यह भूल ही गए, चीजों की कीमतें कम करने की कौन कहें, जो एड-मिनिस्टर्ड प्राइसिज हैं, उनकी कीमतों में बराबर सरकार की ओर से वृद्धि की गई । छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध का कोई इंतजाम नहीं है । दूध की कीमतें पिछले सवावा साल के अंदर केवल दिल्ली में ही तीन बार बढ़ाई जा चुकी हैं । ...सी तरह से मान्यवर, बाहर से गेहूं का

आयात किया जा रहा है । अमेरिका से, कनाडा से गेहूं का आयात किया जा रहा है शायद 580 या 585 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर और इस देश के जो किसान हैं, उनको जो गेंहूं की कीमत दी जा रही है वह कहीं पर 260 है, कहीं पर 265 है और कही पर 255 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है । तो इसके चलते जो इस देश की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हैं, उन पर कोई रोक लगने वाली नहीं है और उनमें बराबर वृद्धि होती जा रही है । इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि श्री मोहम्मद अमीन जी का जो प्रस्ताव है और उसकी जो मूल भावना है, उसको देखते हुए उनको आज ही सदन में घोषित करना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र का वादा था और साथ-साथ इस देश के जो 80–85 प्रतिशत लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो इस देश का कृषक वर्ग है, जो इस देश के मजदूर हैं, इस देश के जो महनतकश लोग हैं उनको आवश्यक वस्तुओं को सस्ते दामों पर मुहैया कराने के लिए सरकार निकट भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है ।

मेरे पास भारत सरकार के विज्ञापन व दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक पैम्पलैट है, इसमें पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, उनको उचित ठहराने का प्रयास किया गया है । लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा गया है इसमें कि डीजल की जो कीमतें हैं, जिस ओर अभी सुरजेवाला जी ध्यान आकर्षित कर रहे थे, उनकी कीमतों की वृद्धि से इस प्रदेश के आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं, उनकी कीमतों के बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है । लेकिन इसका कुप्रभाव पड़ा और जैसे ही डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई, सब्जी तक महंगी हो गई, खाने के तेल महंगे हो गए और उससे नित्य की जितनी भी वस्तुएं थीं, उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई ।

जहां तक किसान का प्रश्न है किसान इस देश का अन्नदाता है, सारे देशवासियों को किसान अन्न उपलब्ध कराता है, चाहे जाड़े की ठिठुरती सर्दी हो, गर्मियों की लू हो या गहरी बरसात हो, अपना खून-पसीना बहाकर के किसी तरीके से वह उत्पादन करता है लेकिन उसकी जो उपज है, उसका लाभकर मूल्य कौन कहे, उसका वाजिब मूल भी उसको नहीं मिल पाता । अभी सरकार ने अपनी कृषि नीति तैयार की है, उस कृषि नीति का प्रारुप भी बांटा जा चुका है और हमारी समझ में कुछ दिनों में वह कृषि नीती भी सरकार की अपनी नीति हो जाएगी । उस संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए । यह मांग बहुत दिनों से इस देश में चली आ रही है । और इस मांग का समर्थन करीब-करीब सभी राजनीतिक दलों ने किया है । स्वयं इस सरकार के मंत्री श्री राजेश पायलट की भी यही राय है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए । इस देश में बड़े-बड़े उद्योगपति वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से रुपया लेकर के, कर्ज लेकर के उसको अदा नहीं करते है और घोषणा कर देते हैं कि हमारा जो उद्योग है, वह बीमार पड़ गया और उसके बाद उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन इस देश का जो किसान है, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो उसकी फसल चौपट हो जाती है, पाला पड़ गया तो उसकी फसल चौपट हो जाती है, इसी तरह से अगर बाढ़ आ गई तो उसकी फसल चौपट हो जाती है, लेकिन किसान का जो नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार की ओर से नहीं की जाती है ।

इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को बहुत जल्दी ही घोषणा करनी चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और जब जब किसान को प्राकृतिक प्रकोप के कारण उसकी उपज की हानि होगी, नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम सरकार करेगी । मैं अपनी बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा । सिर्फ एक सुझाव और देना चाहूंगा कि यह जो उत्पादन के बीच में और बाजार के जाने के बीच में बहुत से बिचौलिए होते हैं, इन बिचौलियन की

प्रथा को भी समाप्त करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत से मुनाफाखोर हैं, चोरबाजारी करने वाले लोग हैं। यह लोग उसका फायदा उठाते हैं और इस देश का गरीब आदमी पिसता है। इस देश के पहले प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि जो ब्लैकमार्केटियर्स हैं The blackmarketeers should be hanged by the nearest lamp-post.

लेकिन उसका कुछ असर तो हुआ नहीं और इस देश में जो उद्योगपति हैं, सब उद्योगपति को तो मैं नहीं कहता लेकिन जो भ्रष्ट उद्योगपति हैं, जो काला बाजारी में लगे हुए हैं, चोर बाजारी में लगे हुए हैं, वह जनता के खून पर नित्य अपने धन की जो हैसियत है, उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं। इसलिए इस संबंध में सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए और जो कंज्यूमर्स आईटम्स हैं, इनके संबंध में भी विचार करना चाहिए ।, क्योंकि गांव का जो चर्मकार है वह बीस पच्चीस तीस रुप में जूते.चप्पल को बनाकर बजार में भेज देता है लेकिन वही सामान जो बाटा की दुकान में पहुंचाता है वह चार सौं, पांच सौ, सात सौ रुपये तक बिकता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं यदि उनके माल की खपत आसानी से बाजार में हो जाये बिना इन उद्योगपतियों के पास जाये हुए, तो वह जो बनाने वाला है, उसको भी लाभ होगा और जो उपभोक्ता है, उसको भी चीजें सही व कम कीमत पर मिलेंगी। इन सब बातों के साथ में एक बार फिर श्री अमीन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश की सही मायने में जो स्थिति है उसकी नब्ज को पकड़ा है और यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal); Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity. The issue that has been raised through the motion of hon. Shri Mohammed Amin is a burning problem in this country. It has been a burning problem since the beginning of our independence, so to say, barring just a few years in between. But the problem has accelerated beyond proportions after the present Government came to power and resorted to or taken recourse to what has been termed as 'liberalisation', liberalisation to keep it in line with the international phenomenon. But we know what has happened in the erstwhile Soviet Union in the name of liberal views. The clock was set back and in this country also, the same thing has happened in the name of liberalisation. The country has been or is being sold to multinationals, monopoly capitalists—both foreign and national. That has been the policy and its invariable concomitant has been the rising prices. In fact, it has gone beyond the capacity of even those who are in employment, not to speak of the army of the unemployed people and the poor in the countryside who have practically nothing to subsist happily. It is this national situation which called for an urgent attention and entergetic action to redress this indiscriminate rise in the prices through senseless tampering with the economy. But, we know, Sir, what happened during the first one year culminating in the Black Day of December 6th at Ayodhya. I am to raise it because such things really divert our attention from the urgent needs of the common people who are engaged, who are made to be engaged in a fratricidal war by the representatives of the vested interests. Its worst manifestation was seen on December 6th of 1992 perhaps, the blackest day in our country, evnn including January 30, 1948, the day of Gandhiji's assassination. The . point is that our rulers who were to prevent the demolition of the Babri Masjid on the 6th December and the holocaust following that dismal deed equally failed to solve the problem of the country's common people, of more than 80 per cent of the people of the country who either live below the povertyline or just on the povertyline. Let us not speak of those who are just above the povertyline. They are there, and the Government is there to protect their interests, but not the interests of more than 80 per cent of the common people who inhabit the country, who inhabit the country in dismal conditnons and whose conditions

have been made all the more despair by the Government of Mr. P. V. Nara simha Rao, by his Finance Minister. But I should not single out only (he Finance Minister. It is really the Government which is responsible for the entire thing. It is not our good friend. Mr. Kamesh war Thakur, it is not just Mr, Manmohan Singh or Mr. Dalbir Singh, but it is the policy of the Congress (I) Government which is ruling at the Centre and in most of the States in the country. They have brought the country to this pass. And they are manipulating the figures, giving a false picture to the country. Very detailed figures regarding the price situation were given by different speaker,. preceding me. The effect of the hike in the petroleum products was described by a former Petroleum Minister who became a Petroleum Minister because of the manipulations of the CongreSs(I) who had been out of power. Earlier, the policy had been that the import substi tution has been given a good-bye. Now whether under the Dunkel proposals or under some other donkey proposals, I do not know[7], this policy of import substi. tuion has been given a good-bye. Now the imports should be uninterrupted. That is the demand of the United States of America, that is the demarnd of Japan, that is the demand from the side of the European Economic Community count ries. And we are going before them with begging bowls and therefore, we are unable to resist them. Dunkel proposals or no Dunkel proposals, our country's doors have been made wide open for the fore ign goods. There had always been a hankering for foreign goods from the side of those who lead a luxurious life. Now, this Government, because of their consti tutional obligation to uphold a socialist system which was injected into the Cons titution of the country during the dark days of emergency, has made it a com pulsion of what was a luxury for the mo neyed people,

4.00 p.m.

This situation has been brought about, and they say the price rise is under check now; the price is decreasing, according to them. But according to the common man, according to us who are not that common, but even according to our experience, the fact is the other way round. According to them, inflation is being two-digit figure but according to us, judging by the purchasing power of the money, the position is mach Worse. Day by day the value of the rupee has decreased in comparison to the pound, in comparison to the dollar and even then we have to accept that our economy is showing strength because of liberalisation. This liberalisation has been the root of all the evil in our country. Prices have increased liberally, inflation has increased liberally; people's gross income has been reduced liberally and in this atmosphere of liberalisation, the entire country is suffocating because Of this noose of liberalisation, the economic noose that this Government has put around the people of the country.

We know the question of strengthen ing the public distribution system, mak-. lag essential commodities available to. the people at reasonable prices, making them available to those below the po verty line, at subsidised rates, has fallen on deaf ears. This Government is weak ening and weakening the pub lic distribution system. In my own State of West Bengal, because of the vagaries of the system and be cause of the position of the Government of Tndia, the rationing system is in dold rums. The situation is very dismal. People do not get rice. There is. no Wheat in the market and in the ration shops. Sugar is not available from the ration shops in West Bengal which used to have the strongest public distribution system.

Sir, without taking more rime of the House I would only say that in such a situation, the only path open to the people of the country is the path of confrontation with this Government to make it come to senses, to make it reverse its economic policy which is now in favour of menopaly capital, in. favour of the foreign multinationals and in favour of U.S. imperialism, Western European countries and Japan. Unless we are able to do that, Nemesis awaits us and that has to be averted by the united might of

the common people the coming. people, the peasants, the worker. the middle change the youth and the student,. But tor that, there is no other way out of was held in 1980, has been brought throug this dismal situation. Thank you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अमीन ने जो संकल्प उपस्थित किया है, मैं उस संकल्प के प्रति अपने समर्थन का इजहार करने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह संकल्प हमारे देश की गरीब मेहनतकश जनता की रोटी और रोजी की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। हमारी जनता के दुख और कष्टों के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज जब जरूरत इस बात की थी कि हमारी संसद और हमारी सरकार हमारे देश की जनता की इन गंभीर समस्याओं के प्रति अपने आप को सबद्ध करती, इन समस्याओं से जूझने के लिए रास्ते तलाश करती उस समय बदनसीब जनता के दुख दर्द से विलग रहने वाली एक पार्टी ने धर्म और मजहब की सीढ़ियों के सहारे सत्ता पर चढ़ने की कोशिश की और उसके जरिये उस पार्टी ने न सिर्फ हमारे देश की जनता के साथ बल्कि हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी की।

माननीय सदस्य : नाम तो बता दीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हमारी इस संसद के हर सेशन में महंगाई पर चर्चा होती है। **(व्यवधान)** आप महंगाई की चर्चा पर ध्यान दीजिए। **(व्यवधान)**

माननीय सदस्य : आप महंगाई पर बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महंगाई पर ही बोल रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : बोलिए समय बहुत कम है। समय बहुत महंगा है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : समय बहुत महंगा है इसीलिए समय की बर्बादी कर रही हूं। मेरा यह कहना है कि हमारी इस संसद में कई बार महंगाई पर चर्चा हुई है। बहरहाल पांच वर्ष के बाद हमारा देश आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहा है और मैं यह समझती हूं कि हमारा देश जब आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहा होगा तो हम उस वक्त महंगाई की भी स्वर्ण जयन्ती मना रहे होंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : अगर आप उनका साथ देते रहे तो यही होगा। अगर हमें बैठा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। **(व्यवधान)**

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : 6 दिसम्बर को देख लिया। **(व्यवधान)** खून की नदी बहाना चाहते हैं आप। **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महंगाई के सवाल को क्यों भटका रहे हैं इधर-उधर। आम जनता की जिन्दगी की ओर ध्यान दीजिए। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : कृपया शांतिपूर्वक बोलने का मौका दीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह तो महंगाई का गम्भीर सवाल है इस गम्भीर सवाल को मन्दिर और मस्जिद के सवाल से मत अटकाओ। मैं अपने माननीय बंधुओं से निवेदन करूंगी कि कृपया इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए देश की जनता के दुख दर्दों से जरा भी आपको सहानुभूति है तो इस संसद की गम्भीरता को बनाए रखें और इस विषय की गम्भीरता को भी बनाए रखें। आप अपना दिल टटोलें कि आपने जनता के साथ गद्दारी की या नहीं... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : इनको बोलने दीजिए। शांति बनाए रखें। समय बहुत कम है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम इतिहास को देखें तो सन् 1942 में पहली बार हमारे देश की जनता को महगाई का अनुभव हुआ था। उस हिसाब से आज 1992 है यानी पूरे 50 वर्ष हो चके हैं। विक्रम सम्वत् के अनुसार हम 21वीं सदी में निवेश कर रहे हैं आज उसको 50 वर्ष हो चुके हैं यानी ये 50 वां वर्ष महगाई का वर्ष है। कांग्रेस के लोग 21वीं सदी का एक बहुत खूबसूरत सपना हमारे सामने रखते रहे हैं। लेकिन विक्रम सम्वत् के काल में जीने वाला हमारा आदमी, हमारी जनता 21वीं सदी, का 50वां वर्ष अपने जीवनकाल में देख चुकी है। 21वीं सदी के बारे में कांग्रेस सरकार लुभावने और सुनहरे सपने दिखाती रही है। मैं आप से पूछना चाहती हूं कि क्या 1942 में जब भारत छोड़ो आन्दोलन का नारा दिया गया था क्या उस समय हमारे देश की जनता के सामने कम लुभावने सपने नहीं थे। उस समय भी हमारे देश की जनता के सामने इससे भी कई बड़े सपने थे, इससे भी बड़े लुभावने सपने थे, सुनहरे सपने थे। सपने यह थे कि हमारा देश आजाद होगा और हमारा देश खुशहाल सपने और समृद्धिशाली होगा। लेकिन देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश की जनता की जिन्दगी में गुणात्मक रूप से परिवर्तन आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि हमारी समृद्धि और खुशहाली के सपने, समानता और समाजवाद के सपने, सारे के सारे सपने एक एक करके चूर चूर हो गये और आज हम इस मकाम पर खड़े हुए हैं कि जब एक बार फिर साम्राज्यवादी देश की धरती पर आकर अपना पंजा गाड़ना चाहते हैं, हमारी संप्रभुता और सार्वभौमिकता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आज शायद फिर वही समय आ गया है जब हमें फिर ये नारा लगाना पड़े कि साम्राज्यवादियों, हिन्दुस्तान छोड़ो।

जब से यह नई सरकार आई है, इस नई सरकार के आने के साथ ही कई नये नारे दिये गये हैं। कई नई नीतियां घोषित की गई हैं। नई आर्थिक नीति नई शिक्षा नीति, नई दवा नीति, नई खेल नीति और यहां तक कि अब नई सांस्कृतिक नीति की भी घोषणा की गई है। हमारा अनुभव यह है कि हम दूरदर्शन पर देखते हैं कि नया लक्स, नया सन्फ, नया क्लोज अप, अल्ट्रा सर्फ, इन विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ता को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है और हमारी कांग्रेस सरकार भी इन नई आर्थिक नीतियों के लबादे में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, शायद वह नया रास्ता तलाश कर रही है। लेकिन इन विज्ञापन की चमक दमक के पीछे धोखे के अलावा कुछ नहीं होता है। हमारी सरकार की नई नीतियां धोखे के सिवाय कुछ नहीं हैं। इनमें ऊपरी चमक दमक के सिवाय कुछ नहीं है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जब भी नई आर्थिक नीतियों की चर्चा करते हैं तो इस बात को कहना कभी नहीं भूलते हैं कि न्यू इकनोमिक पालिसी विद ह्यूमन फेस। नई आर्थिक नीति मानवीय चेहरे के साथ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वे जब भी नई आर्थिक नीतियों की घोषणा करते हैं तो इस बात को कहते हैं कि जो भी नया सृजनात्मक परिवर्तन करेंगे, जो भी आर्थिक समायोजन करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, जो भी ढांचागत परिवर्तन करेंगे उन ढांचागत परिवर्तनों से हमारे देश की गरीब जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि इन ढांचागत समायोजनों की हमारे देश की गरीब जनता पर भारी असर पड़ेगा? इन नई आर्थिक नीतियों का हमारे देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा! उसका सबसे बड़ा परीक्षण महंगाई है। महंगाई का आलम क्या है? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि हमारे वित्त मंत्री कहेंगे कि ऐसा नहीं है। मैं उन्हें कुछ तथ्य देना चाहती हूं। पिछले वर्ष

1991-92 में जिन चीजों के दाम बढ़े उन चीजों में सबसे ज्यादा दाम आम जनता की रोजमर्रा की जरुरत की चीजों पर बढ़े। खाद्यान्न के बढ़े। 1991-92 में थोक सूचकांक में सबसे ज्यादा वृद्धि खाद्यान्नों पर 30.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्यान्नों में भी गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि 26.9 प्रतिशत हुई। इसके अलावा दालों की कीमतों में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूध का दाम 13.1 प्रतिशत बढ़ा और फलों और सब्जियों में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंडा, मछली और मांस के दामों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन नीतियों के संबंध में जो ये घोषणा करती है कि हमारी आर्थिक नीतियों का चेहरा मानवीय है, इनकी आर्थिक नीतियों के मानवीय चेहरे की पोल सिर्फ इस बात से खुल जाती है कि 1991-92 में खेतीहर मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री संघ प्रिय गौतम : यह पोल तो तो ऐसे भी खुल जाती है कि उधर केवल एक सदस्य बैठे हैं। सत्ताधारी पक्ष में इतना इंटेरेस्ट है कि वे भी सो रहे हैं... **(व्यवधान)**।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : जो सदस्य जागे हुए हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब कि थोक मूल्य... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप खत्म कीजिये। आपका समय हो चुका है। तथ्य आप न दें। मंत्री महोदय के पास तथ्य होंगे। आप अपनी बात कहें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : वित्त मंत्री महोदय के पास दूसरे तथ्य होंगे और वे मेरे को कहेंगे कि आपके तथ्य सही नहीं है। इसलिये मैं कम से कम हाउस को बता देना चाहती हूं कि ये तथ्य हैं। मंत्री महोदय किस तरह से तथ्य बनाकर लायेंगे यह मालूम नहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं जाती हूं मंहगाई और मुद्रास्फीति में पहलू पर। पिछली 14 जुलाई को हमारे इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री ठाकुर साहब ने, जो यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ यह घोषणा की कि हमारी नयी आर्थिक नीति सफल होने लगी है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आ गयी है, यह 13.6 से 11.1 प्रतिशत पर आ गयी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अखबारों में आये इस छोटे से तथ्य से हमारे ठाकुर साहब इतने उत्फुलित हुए कि उन्होंने आई० एफ० को जो मेमोरेंडम दिया, उस मेमोरेंडम में उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में हम मुद्रास्फीति की दर को सिंगल डिजिट में ले जायेंगे, दहाई से इकाई में ले आयेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि दहाई से इकाई में लाने के लिये वे कौई से कदम उठा रहे है? कौन से रास्ते हैं जिनके जरिये मुद्रास्फीति डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पर आयेगी? हालत क्या है, इस बारे में मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। पिछले जून महीने में, इस वर्ष अप्रैल से जून तक के इन तीन महीनों में जिन चीजों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े उनमें 36 सामग्रियों की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इनमें से भोज्य पदार्थ, खाद्यान्न और तेल यानी आम जनता की जिन्दगी में काम आने वाली, रोजमर्रा उपयोग में आने वाली चीजों के दाम बढ़े और इन्हीं चीजों के दामों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और हमारे वित्त मंत्री महोदय हमको आश्वासन दे रहे है कि नहीं, मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय' हालत तो यह है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन में बराबर गिरावट आ रही है। पिछले वर्ष 0.1 प्रतिशत की गिरावट आयी थी और इस बार अनुमान यह लगाया

जा रहा है कि .6 प्रतिशत की गिरावट आयेगी और अगर अयोध्या का मसला ऐसे ही चलता रहा तो न जाने देश के औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट आयेगी। ऐसे ही अगर सब जगह कर्फ्यू लगता रहा तो इससे औद्योगिक रिसेसन की बातें होने लगी हैं, औद्योगिक मंदी की बातें होने लगी है। ...(व्यवधान) आप क्या करके मेरी बात सुन लीजिये और जो सच्चाई है उससे नजरें मत चुराइये। ...(व्यवधान)...आप कर्फ्यू लगायेंगे तो इससे क्या महंगाई कम होगी? उद्योग धंधे बंद होंगे तो क्या महंगाई कम होगी?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सरला जी, अब आप खत्म कीजिये।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय मैं चाहूंगी। मेरा सारा समय लिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि खत्म कीजिये। ...(व्यवधान)...देखिये मैं कितना बोली हूं और आप लोगों ने कितना समय लिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप उनकी बात पर गौर मत कीजिये और अपनी बात को खत्म कीजिये। सरला जी, यह प्राइवेट मेंबर संकल्प है। इसका समय निर्धारित है। इतनी बात इस पर हो चुकी है अब हम मंत्री जी को सुनना चाहेंगे। अगर सदस्य अपनी बात जल्दी नहीं खत्म करते हैं तो मंत्री जी को नहीं सुना जायेगा। सरकार का भी इस पर वक्तव्य आना चाहिये। आप खत्म करें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सरकार का वक्तव्य मैं सुनना चाहूंगी। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : 5 बजे तक हमें इसको खत्म करना है। आप और दूसरे मेंबर अगर 4.30 तक खत्म नहीं करेंगे तो मंत्री महोदय कब इसका जवाब देंगे?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से सरोकार नहीं है, मुझे इस बात से सरोकार है कि मुझे कितना समय दिया जा रहा है और मैं अपने समय को सही रूप में इस्तेमाल करना चाहती हूं। उसमें कोई कटौती नहीं करना चाहती हूं और माननीय मंत्री महोदय को भी सुनना चाहती हूं क्योंकि यह हमारे देश की जनता की समस्याओं का सवाल है इसलिए निश्चित रूप से हम उनको सुनना चाहेंगे। आप माननीय सदस्यों से निवेदन करें कि वे शान्ति बनाए रखें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बात को कहना चाहती थी कि वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिये हमारे वित्त मंत्री राज्य हमें इस बात का दिलासा दे रहे हैं कि वे डबल डिजिट से सिंगल डिजिट मुद्रास्फीति की दर ले आएंगे। हालत क्या है। औद्योगिक मंदी का आलम आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, विदेशी मुद्रा कोष संकुचित होता जा रहा है, विदेशों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे है कि मंहगाई घटा देंगे। हालत तो यह हो गई है कि आई०एम०एफ० द्वारा ला दी गई शर्तों को अनुसार आप अपना राजकोषीय घाटा कम करने पर अपने सार्वजनिक उद्यमों के शेयर मिट्टी के दाम बेच रहे हैं। जिस समय शेयरों की कीमतें बाजार में ऊंची थी उस समय भी आश्चर्य होता है कि सार्वजनिक उद्यमों के शेयर मिट्टी के दाम पर बेचे गये। जनकी रामन कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को बेचने की मोडेलिटीज तय करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस के चेयरमैन कौन थे? वही कृष्णामूर्ति जिनका संबंध शेयरों में धांधलियां करने वाली फेयरग्रोथ कम्पनी से था। जहां भ्रष्टाचार का यह आलम

है, वहां काले धन पर आप किस तरह से काबू पायेंगे, किस तरह से आप मंहगाई पर काबू पायेंगे ? इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आज के इन हालात में जब लाखों लोग काम से हाथ धो रहे हैं । बेरोजगारी की समस्या वैसे ही इतनी गम्भीर है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही आई०एल०ओ० और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में एक सेमिनार हुआ था । उस सेमिनार में यह बात उभर कर और स्पष्ट रूप से सामने आई भी कि जो नयी आर्थिक नीति लाई जा रही है या जिस नये ढांचे का समायोजन किया जा रहा है, इसके चलते लाखों लोग बेकार हो जाएंगे, लाखों मजदूर बेकार हो जाएंगे । उन्होंने तथ्य दिया था कि 1992-93 में 30 से 40 लाख लोग बेकार हो जाएंगे । मेरा सवाल है कि इन लाखों बेकार लोगों को आप काम कहां से देंगे, कहां उनके लिये रोजगार के अवसर पड़े हैं ? एक तरफ उद्योग धन्धे बन्द होते जा रहे हैं, सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों को आप बेच रहे हैं तो सवाल यह है कि आप अपनी सम्पत्ति को, सरकार अपनी सम्पत्ति को, हमारी मेहनतकश जनता के खून पसीने से कमाई हुई सम्पत्ति को, मिट्टी के दाम पर बेच रहे हैं दूसरी ओर आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर हमारे देश की जनता की जरूरत की चीजों पर सब्सिडी को कम कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नाम-मात्र को रह गई है । बाड़मेर का आप उल्लेख करते हैं । आप हालत तो देखिये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन उपलब्ध नहीं है, केरोसीन उपलब्ध नहीं है, उनके बाहर लाइनें लगी हुई हैं जहां हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं । इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उस संकल्प का मैं समर्थन करती हूं, ताईद करती हूं । मैं वित्त राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया यह बताएं कि 1993 के लिए कौन सा भावी खाका उन्होंने तैयार किया है जिससे हमारे देश की जनता को यह विश्वास हो सके कि आने वाला 1993 का वर्ष उनके लिए शायद थोड़ा सा सुकून ले कर आएगा और उनकी जिन्दगी की जो हालत है उसमें कम से कम थोड़ा सुकून अवश्य वे दे सकेंगे । इस बात पर वित्त मंत्री जी जरूर रोशनी डालेंगे । धन्यवाद ।

श्री इश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ती हुई मंहगाई और जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, इसके संबंध में हमारे विद्वान मित्र मोहम्मद अमीन साहब की जो चिंता है, वह पूरे सदन की चिंता है और पूरे देश की चिंता है । लेकिन केवल एक को चिंता नहीं है, केन्द्रीय सरकार और इसके वित्त मंत्री को इसकी चिंता नहीं है । इन्होंने जब राजपाट सम्भाला था तो यह कहा था कि हम 100 दिन के अन्दर मंहगाई को घटा देंगे । लेकिन इन लोगों ने मंहगाई घटाने की बात कौन करे, इस समय सौ गुना मंहगाई बढ़ा दी है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महेन्द्र मोहन) : मंहगाई के बारे में बात हो रही है । (व्यवधान) आप कहते जाइये ।

श्री इश दत्त यादव : मान्यवर, इस समय इन्होंने सौ गुना मंहगाई बढ़ा दी है । अगर इनकी नीतियां यही रहीं—हम इनके जाने की बात तो नहीं कहते क्योंकि मजबूरी है अभी कुछ दिन इनको जिंदा रखने की लेकिन अगर इनकी नीतियां यही रहीं और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में, उनकी जी-हुजूरी में ये काम करते रहे तो हमारा विश्वास ऐसा है, अंदाज भी ऐसा है कि यह मंहगाई हजार गुना बढ़ा देंगे । मान्यवर, वित्त मंत्री जी, बड़े वित्त मंत्री जी, जो खजाने के बड़े वित्त मंत्री जी हैं वे तो नहीं हैं शायद छोटे मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर जी जवाब देंगे और मैं इनका जवाब भी जानता हूं । जो इनके

अधिकारी लिखकर देंगे कि महंगाई इज ए इंटरनेशनल फिनामिना । फिर बोलगे महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है । लेकिन दवा महंगी, गेहूं महंगा, चीनी महंगी, कपड़ा महंगा, डीजल महंगा, पैट्रोल महंगा । यह जो हो रहा है इसमें कहीं कमी आने वाली नहीं है । इनका ग्राफ भले नीचे गिरता चला जाए । इस महंगाई का कारण क्या है । माननीय वित्त मंत्री जी समझते होंगे । खती से संबंधित हैं । लेकिन इनके अधिकारी लोग जो इनकी रिपोर्ट को बनाकर देंगे, जो बयान बनाकर देंगे, व एयर कंडीशन्स कमरों से बनाते हैं । उन्होंने खेत नहीं देखा है, बरसात नहीं देखी है । गेहूं कैसे बोया जाता है, काटा जाता है इनको मालूम नहीं है और मान्यवर दावे के साथ कहता हूं कि इनके अधिकारी जो इनके बयान को तैयार करेंगे और जो देश का मूल्यांकन कर रहे हैं, महगाई का कर रहे हैं उनको अगर गांव में लेकर चले जाएं तो गेहूं और जौ की फसल में फर्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सी गेहूं की सफल है और कौन सी जौ की । महंगाई इसलिए देश में बढ़ रही है और महंगाई इसलिए बढ़ी है कि देश का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया । जब तक देश का उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा देश से गरीबी और महंगाई मिटने वाली नहीं है देश में जो गरीबी है, महंगाई है इसका संबंध उत्पादन से है । उत्पादन से इस सरकार का कोई मतलब नहीं है । मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने और विश्व बंधु बापू ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उत्पादन में जितना सामान है सब पृथ्वी माता के गर्भ के अंदर रहता है । यह लकड़ी है, जमीन से निकली । लोहा जमीन से निकला । घड़ी हम लगाये हैं, इसका लोहा जमीन से निकला । अनाज जमीन से निकला । कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी माता के गभ से नहीं निकलता है। इनको निकालने का प्रयास करना चाहिए । था । इस सरकार ने इसका प्रयास नहीं किया । कारखाने लगाने पर जरूर जोर दिया । आप कारखानों की नगरी से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं । कारखाने उत्पादन नहीं करते हैं । कारखाने शकल बदल देते हैं । जमीन का जो लोहा है उसको निकालकर वे घड़ी बना देंगे, साइकिल बना देंगे, रेल का इंजिन बना देंगे लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे । उत्पादन तो जमीन के अंदर से होता है । जमीन के अंदर से उत्पादन को करने के लिए इस सरकार के लोगों ने 40–45 साल में कोई ध्यान नहीं दिया । देश का उत्पादन घटा है । इस वक्त तो और उत्पादन घटने की नौबत आ गयी है ।

मैं भी एक छोटा मोटा किसान हूं और बीच बीच में हर हफ्ते अपने खेत पर स्वयं काम करता हूं । इन्होंने खाद के दाम बढ़ाए हैं । मेरी कैपेसिटी नहीं रही है और मेरे जैसे अनेकों किसान जो हैं जिन्होंने पिछले वर्ष अपने गेहूं के खेत में खाद डाली थी लेकिन इस साल डालने में समर्थ नहीं है । किसान कह रहे हैं कि हम गेहूं नहीं बो पाएंगे, हम इसकी जगह चना बो लेंगे, मटर बो लेंगे क्योंकि खाद तो मिलेगी नहीं । जब खाद महंगी मिलेगी, हम खरीद नहीं सकते तो हम गेहूं क्यों बोएंगे । हम जो लागत लगाएंगे उससे हमारा उत्पादन कम होगा । इसलिए किसान मजबूर हो रहा है मटर और चना बोने के लिए । देश में गेहूं का उत्पादन कम होगा । यह सरकार तो भिखारी सरकार है ।

श्री शिव चरन सिंह (राजस्थान) : उत्पादन कम नहीं होगा तो इम्पोर्ट कैसे करेंगे ।

श्री ईश दत्त यादव : यह सरकार तो भिखारी सरकार है । इस सरकार में हया और शर्म भी नहीं है कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए । जब संकट आएगा अन्न का, हमारे विदेश मंत्री विदेश रवाना हो जायेंगे सब तैयारी करके और फिर वहां आई०एम०एफ० से, विश्व बैंक से, विश्व बैंक मुद्रा कोष से करजा मांगने लगेंगे, फिर ले आवेंगे ।

अब गेहूं ले आए केनेडा से, मनों गेहूं ले आए। हमारे देश के किसान को 350 रुपये क्विंटल देने के लिए तैयार नहीं हुए और 550 रुपये क्विंटल के हिसाब से वहां से गेहूं खरीद ले आए। इस सरकार को शर्म, हया नहीं है। इस देश के किसान का इन्होंने सम्मान गिराया है।

इसलिए, मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक इस देश के किसान की ओर आप ध्यान नहीं देंगे---आपने डीज़ल महंगा कर दिया। अब जो पंपिंग सैट डीज़ल से चलते हैं, उसमें कमी आई है। डीज़ल खरीदने में समर्थ नहीं है, अपने खेतों की सिंचाई करने में अब समर्थ नहीं है। डीज़ल आपने महंगा कर दिया विश्व बैंक और इंटरनेशनल मुद्रा कोष के दबाव में।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी कह रहे थे, जिस दिन विदेश मंत्री हमारे, विदेश को रवाना होते हैं बैंक से करजा मांगने के लिए, उस दिन यहां घोषणा करके जाते हैं कि हम पेट्रोल का दाम महंगा कर रहे हैं, हम डीज़ल का दाम महंगा कर रहे हैं, हम रसोई में जलाने वाली गैस को महंगा कर रहे हैं। जैसे यहां पर यह तोहफा देकर जाते हैं, वहां विश्व बैंक में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में फिर भीख मांगते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था, अब दूसरे मंत्री जी भी चले गये। कांग्रेस के लोगों की इसमें कोई रूचि नहीं है। दो-तीन मेम्बर बैठे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कृषि का उत्पादन इस देश के अंदर नहीं बढ़ेगा, महंगाई तब तक इस देश से जाएगी नहीं। जब तक कांग्रेस की पार्टी अपने नीतियों को नहीं बदलेगी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए अच्छी नीति नहीं रखेंगी, तब तक इस देश से महंगाई जाने वाली नहीं है।

मान्यवर, इस देश के मनीषी, दार्शनिक, राजनेता थे स्व० डा० राम मनोहर लोहिया। डा० राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत है कि अगर उत्पादन में एक रुपया खर्च होता है, लागत मूल्य एक रुपया है, तो देश के किसी कोने में भी वह सामान डेढ़ रुपये से अधिक में नहीं बिकना चाहिए। हालत क्या है? मान्यवर, किसान का लागत मूल्य तो आप दे नहीं सकते। मैं केवल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देना चाहता हूं। बी०जे०पी० के भाई लोग नाराज नहीं होंगे, इसमें केंद्र सरकार की भी गलती रही और गलती बर्खास्त होने वाली सरकार की भी रही है। किसान ने गन्ना पैदा किया, गन्ना चीनी मिलों को दिया, चीनी तैयार हो गई। गन्ना बिक गया। तीन सौ करोड़ रुपया बकाया रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में जब आंदोलन खड़ा हुआ, तो थोड़ी सी राशि किसान को दी गई। अब किसान सोच रहा है कि गन्ना हम किस लिए बोयेंगे, गन्ने का उत्पादन किस लिए करेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: महोदय, मैं यह कहना... (**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव: आप बैठिये। आपका स्वभाव है डिस्टर्ब करना। आप जब इतना चिल्लाये, तो मैं तो नहीं बोला।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): यादव जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसान सोच रहा है कि अब गन्ने का उत्पादन न करें, गन्ने का उत्पादन कम करें।

मान्यवर, श्री रामेश्वर ठाकुर जी जानते हैं गन्ने का उत्पादन जब कम हो जाएगा, तो फिर आप विदेश भागेंगे, कटोरा ले जाएंगे कि हमें चीनी दो। हम हिंदुस्तान में चीनी महंगी बेचेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि डा० लोहिया, चौधरी चरण सिंह और महात्मा गांधी की जो नीति रही, जो सिद्धांत रहा—अन्न के उत्पादन को बढ़ाओ और दूसरा, जो डा० राम मनोहर लोहिया की नीति रही—कारखाने के अंदर जो सामान तैयार होता है, फिक्सेशन आफ प्राइस करो। कभी इस सरकार ने कोशिश की? कपड़े के दाम किस तरह से हैं? साधारण सी रुपये की है। दुकानदार बोलेगा, हम डेढ़ सौ रुपये में देंगे। हम मोल-भाव करेंगे, तो 120 रुपये में हमको दे देगा।

दवा के दाम पर तो कोई बहस कर ही नहीं सकता, चाहे दवा जीवित हो, चाहे डेड है, चाहे एक्सपायरी डेट के बाद वाली हो। जो आदमी नहीं जानता है,... (समय की घंटी)

मैं खत्म कर दूंगा, मैं आपकी बाध्यता, समय की बाध्यता और विन मंत्री जी के भाषण की भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था दवाओं के संबंध में। दवाओं का कोई रेट है सरकार के पास—न बुद्धि है, न विवेक है और न नीति है कि दस-बीस सैंकड़ा दुकानों का जरा छापा मरवा करके देख लें। फेक दवाएं बिक रही हैं, महंगी बिक रही हैं, दवाओं का कोई रेट फिक्स नहीं है। कारखानों के अंदर जो सामान बन रहा है, कारखानों के अंदर बने हुए सामान का कोई निरधारण नहीं किया जाता है। किसान का जो उत्पादन होता है, उसका लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं। साढ़े चार सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन हुआ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वैज्ञानिकों ने कहा, आचार्य चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय, कानपुर के वैज्ञानिकों ने कहा कि 425 रुपये से लेकर 450 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान का लागत मूल्य लगा है। गेहूं के उत्पादन में सरकार साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल देगी, तो उत्पादन इस देश का घटेगा। महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए मान्यवर आपको घंटी न बजानी पड़े मैं आपके माध्यम से माननीय विन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देश की जनता के बारे में सोचें किसानों के बारे में सोचें उत्पादन के बारे में सोचें और एक ही तरीका है कृषि का उत्पादन बढ़ाइये और दूसरा तरीका है कि लघु उद्योगों का जाल बिछाइये। छोटे उद्योगों में छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योगों में जो सामान तैयार होते हैं उनको बड़े कारखानों में तैयार होने से रोकिए, ताकि महंगाई पर आप कंट्रोल करें गरीबी को मिटा सकें। वरना आपको तो जाना ही है। आप तो इस देश की विवशता हैं इस देश की लाचारी हैं और देश के कंधे पर आप बैठ करके मौज और मस्ती ले रहे हैं। आप एक कलंकित सरकार के रूप में आखिर एक दिन चले जायेंगे।

मान्यवर मैं अंतिम अनुरोध कर रहा हूं कि फिर से आप ध्यान दीजिए महंगाई पर रोक लगाने के लिए और अपने विद्वान साथी, सम्मानित साथी मोहम्मद अमीन साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक ज्वलंत समस्या पर इन्होंने संकल्प प्रस्तुत करके इस सदन का और इस देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन प्रयास तभी सार्थक माना जाएगा जब सरकार के कान पर जूं रेंग जाए। धन्यवाद।

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh); Mr. Vice-Chairman the resolution of Mr. Mohammed Amin in price-rise is a timely one and it deserve support from everyone in the House because wherewer you go you will find that people are suffering under a high inflation, high price-rise and also, in some cases. due to scarcities of essentrial commodities

It is not only a one-time affair. For the last two years, prices have been going up. More than 30 per cent of the increase in the inflation rate has been already recorded. And on this 30 per cent increase, we are having the phenomenon of the present increase. Though our Finance Minister very often says in Parliament and outside that they are trying to bring the inflation rate down to a single digit, that does not mean that really our prices are increasing at a single-digit rate. They are increasing over the already increased base of 30 per cent. Now, In this background, the suffering of people due to a high price is phenomenally increasing. Perhaps, the Government also, because of their policies, economic policies, pre unable to contain the price-rise. They have not kept their promise of bringing the prices to a normal level. As you know, people are restive. Wherever prices increase, wherever the economy falters, the ruling party will suffer a defeat. The Government must have noted the recent elections in the United States. Bush, who was having a very high popularity rate a bit earlier, a few months back, lost the election, not because of any foreign policy failures but because of economic policy failures. And, there was a recession in the United States and people wanted to change the, Government. They elected a new President because of some promises made by him. In our country, we are faced not only with recession but also with inflation. Everybody knows it. As far as I understand, the inflation rate in ween three per cent and four per cent. But here, even at present, it is anywhere between nine ptr cent and ten percent. In this background, our country is facing not only inflation but also stagnation. So it is a stagnation scenario. The Government has no policy and they say that they are following a policy of containing excess demand through fiscal discipline, I would like to know whether the Gov-ment is really following this type of discipline in Its fiscal policy. The growth rate in the economy is only 2 per cent but the money supply which they pumped into the economy is 18 per cent. So when money supply is released to the market when the growth rate in the economy

1s only 2 per cent, naturally it increases

the price, it increases the inflationary rate. So the Government owes an explanation to the Parliament. Let them speak the truth. They may be under compulsion by the World Bank or the IMF to contain inflation. Whoever advises, I appreciate him for his advice. But the Government is not following that advice which is useful at least as far as people are concerned. The main reason is that they are printing more notes, they are releasing more money and that is why inflation is increasing in our country.

Secondly, because of the price rise, the purchasing power of the people is going down. There is a paradoxical situation in our economy. Recently I had been to Punjab besides my own State of Andhra Pradesh. There is a serious unrest among the peasant community. While we are agitating for bringiny down the prices of essential commodities, the peasants are agitating for increase in the prices. So in Andhra Pradesh, as far as I known, last year, cotton was selling at around Rs. 1500 per bale but this year it is selling at about Rs. 1000 per bale. Similarly, wheat price in Punjab last year was almost touching Rs. 100 per quintal. This year it is only Rs. 350 per quintal. This also must be noted against the background of their increase in the fertilizer prices. This is also part of our resolution So fertilizer prices have been increased because they cut down the subsidy. Whom are they giving subsidy? Are they giving subsidy to peasants? No. They are giving this subsidy to the industry which is a junk industry, which was never modernised and no technological upgradation was there. So instead of modernising the technology in the fertilizer industry, they have been subsidising in the interest of some public sector units and also private sector units for their own benefits. Because of these subsidies naturally they were not in a position, they were not inclined, to develop their technologies in order to meet not only the international standards but even our own standards. Yesterday, I read a statement by a Minister though there was no Question Hour- According to this, the productivity of a worker in India is about 800 dollars whereas the productivity of a worker in Pakistan is more than 1400 dollars. Besides, there are many developed countries

where the productivity per worker may be 10,000 dollars or 15,000 dollars or 20,000 dollars. That is the rate of pro ductivity in those countries. We may not be able to compare ourselves with those with those developed countries. We are the lowest in terms of productivity as far as Asian countries are concerned. I am not talking about other countries. So because of Government policies, because of subsidising such backward industries, because of not taking up the moderni sation, the technological upgradation, this paradosical situation Is developing. So on the one and, in general, the people are suffering on account of high prices, on the other, the peasants in the rural communities are suffering for lack of proper prices. What is the policy of the Government? In the recent past, at least, since this Government has com., the balance between trade and industry is again shifting in favour of industry. Though the people are suffering due to high prices in one respect, the peasants are suffering in more than one respect due to lack of proper prices. So the market forces do net operate there. The Government is intere sted in making exports. Cotton is avai lable in our country. In our State they can export cotton and the peasants may get a remunerative price. They don't allow cotton to be exported because they want to pamper the millers here to get cotton at low prices. The Govern ment's policy is to help the backward industry. Really, they don't warn market forces to operate though they talk of developing the market forces. These market forces work only in favour of top business community. They don't help the poor peasants. They don't help the common man. They don't help even the small industrialists. There types of wrong economic policies they have been following. Inflationary pressures are increasing in our economy. So I want to make a request to the hon. Minister. The Ruling Party Members are not here because they do think that these Private Members' Resolutions are not very important But tomorrow if they go to their constituencies, people will ask them why the prices are increasing. Every Member of the Ruling Party is answerable. The Op-

position people think, since trey are not in the Government, people may not ask them. But the Ruling Party is answerable. What they have been doing to develop the economy, to provide more employment, to reduce the prices, to give more opportunities, at least to the extent necessary to meet their requirements—all these questions will be asked by the people and they are answenable. This is a time-bomb for them. If they don't defuse it properly in time; they will be blown up in the coming period. Even in the last hour I request the Government to ponder over these matters and come to a satisfactory solution in the interest of helping the poor people and the peasants.

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को कहूंगी। चूंकि बहुत बात हो चुकी है दोहराने की कोई जरूरत नहीं है और न ही मैं स्टेटिस्टिक्स देने जा रही हूं वैसे मेरे पास थीं तो बहुत लेकिन अब समय नहीं है। मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। हमारे देश की आर्थिक हालत तो बहुत खराब थी पहले से ही बीच में कुछ सुधरी थी जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने पहले कहा, लेकिन पिछले दिनों में जबसे यह नई सरकार आई नरसिंह राव जी की तो इन्होंने तो इस देश का भट्टा ही बैठा देने का फैसला कर लिया है। इन्होंने भट्टा इसलिए बैठाने का फैसला किया कि विदेशों से जिनसे कर्जा लेने का इन्होंने फैसला किया इंटरनेशनल मोनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक से उनके हुकुमनामे के मुताबिक इन्होंने अपने देश की सारी अर्थनीति की रिस्ट्रक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। दुनिया में महोदय 80 देश 80 डवलपिंग नेशन्स ऐसे हैं जहां यह रिस्ट्रक्चरिंग का काम शुरू हुआ है। मुझे उसमें से कुछ देशों को देखने का मौका भी मिला है। उनमें से कोई एक मिसाल नहीं कि किसी एक देश में भी रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उनकी हालत सुधरी हो। कुछ ऊपर वाले अच्छी हालत में रहे और बाकी नीचे वाले लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग जिनकी आर्थिक हालत खराब थी उनकी हालत

और बदतर होती गई। हमारे देश की हालत भी यही हो रही है। हमने एक मिडिल क्लास तैयार कर दिया हैं और एक ऊपर के लोग पांच करोड़ लोग अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं ऐसा कर दिया और अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, अब हम बात कर रहे हैं ओपेन डोर पालिसी की, अब हम बात कर रहे हैं विदेश से आयात की। विदेश में निर्यात तो हम करेंगे नहीं एक्सपोर्ट हम कुछ कर नहीं रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे देश के एक्सपोर्ट का करीब-करीब पचास परसेंट एक्सपोर्ट कृषि-जनित उत्पादन का ही हैं। हम मसाला बेच रहे हैं हम प्याज बेच रहे हैं हम लहसुन बेच रहे हैं और विदेशों से हम सामान मंगवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हिन्दुस्तान को हम दुनियां के लिए बाजार में एक खरीदगी करने का बाजार बना रहे हैं। जो इस दुनियां के विकसित देश हैं---जी-7 कंट्रीज और जो दूसरी देश हैं विकसित देश, उनके उत्पादन के लिए हम बाजार बनेंगे। और तो और जो विकसित देश नहीं थे पिछले दिनों तक---मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, ये सब छोटे-छोटे देश, जिनकी माली हालत हमसे खराब थी, पिछले 20 बरस में इनकी माली हालत हमसे सुधर गई है और उनके लिए भी हम बाजार बन गए हैं। यह हमारी ओपन डोर पालिसी का नतीजा होगा और नतीजा क्या होगा कि रुपए को हम, दूसरे देशों के पैसे के साथ उसका बदलाव करने के लिए तरीका अपना रहे हैं। आप रुपए का बदलाव क्या करेंगे? मैं हाल ही में जापान गई हुई थी एक सम्मेलन में। एक येन का दाम, एक येन में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, वहां शायद एक बीड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक येन की कीमत 28 नए पैसे है हमारे देश के। आप बदलाव करेंगे, उससे उपलब्धि क्या होगी? उसी प्रकार से एशिया के देशों के साथ भी अगर आप करें तो हमारे रुपए की कोई कीमत नहीं है। हमारी पर कैपिटा इन्कम, हिन्दुस्तान का पर कैपिटा इन्कम शायद बंगला देश और नेपाल को छोड़कर, बाकी सबसे कम है। हम किसके साथ मुकाबला करने की बात कर रहें हैं? किसके रास्ते पर हम जाना चाहते हैं? हमें खुशी होती अगर यह सरकार कहती कि गांधी जी जो कहते थे कि ग्राम स्वराज्य की बात करो, स्वावलम्बन की बात करो, अपनी जरुरत की चीजों का खुद उत्पादन करो, अपनी जरुरत की चीजों को अपने देश के लोगों को मुहैया कराओ, खेत में पानी का उपाय करो, अपने देश में छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ाओ, 18 करोड़ इस देश के नौजवान, जो आज अंडर एम्प्लायड और अन एम्पलायड है उनके हाथ में रोजी और रोजगार दीजिए। तो मैं यह कह रही हूं कि हमारा दल, जनता दल, सरकार की नीति, औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति का विरोध करता है और यह इस सदन में हमने बार-बार कहा है। महोदय, आप एक-एक बात विदेशों के कहने पर, ठीक है, यह दलील देंगे कि गल्फ वार हुआ था इसलिए हमको पैट्रोल का दाम बढ़ाना पड़ा। हमारा बैलेंस आफ पेमेंट बहुत ज्यादा था, जो हम कर्जा लेते हैं उसका हमको सूद चुकाना पड़ता है और इसलिए हमको कर्जा लेना पड़ता है। यह तो वही हालत हो गई, संस्कृत में एक श्लोक है :---

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्।
ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्॥

कर्जा लेकर घी पीओ और आराम से जिंदा रहो और कर्जे का बोझ अपने आने वाले बच्चों पर छोड़कर जाओ। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आज का दिन तो हम 'eat, drink and be merry'.

यह इकनॉमिक पालिसी हमारी है। आज का दिन हमारा खुश रहे, हम आराम से रहें, हमारी कुर्सी बरकरार रहे, बस। जहन्नुम में जाए देश, उससे कोई मतलब नहीं। तो आज यही हो रहा है और जब तब यह आर्थिक नीति, यह ग्लोबलाइजेशन की इकॉनमी इनकी, न्यू ग्लोबलाइजेशन की पालिसी, यह नयू मार्किट ओरिएन्टिड पालिसी, इसमें जब तक तबादला नहीं आएगा, तब तक हालत में बहुत सुधार

होने वाला नहीं है । बहुतों ने बहुत कुछ कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, मुझे केवल इतना ही कहना था । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI MD. SALIM): We ade still having three names before us. Shri Khaleelur Rahman.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, हमारे मुअज्जिस दोस्त और साथी जनाब मोहम्मद अमीन ने जो रेजोल्यूशन मूव किया है, मैं उसकी भरपूर ताइद करता हूं । इस वजह से कि इस सूरतेहाल की असल जिम्मेदार वही हुकूमत हो सकती है जो पिछले 45 बरसों में सबसे ज्यादा, करीब-करीब 40–41 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करती रही । जाहिर है कि उस हुकूमत की जो इकोनोमिक पालिसी रही है, उस हुकूमत की इम्पोर्टपालिसी, उस हुकूमत की एक्सपोर्ट पालिसी, वे सब जिम्मेदार हैं कि हमारे मुल्क में जो जरूरी आ गया है, 'मिसाल के तौर पर खुर्दनी तेल है' और अनाज की कीमतें हैं और फिर पैट्रोल की कीमतें हैं, यह सब इन्हीं पालिसियों का ही नतीजा है कि इनकी कीमतें दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं । आप यह देखेंगे कि हमारे मुल्क की जो सोसाइटी है, उसका तसव्वुर जो है वह सोश्यलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी है और इस सोश्यलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में हुकूमत की जो इकनोमिक पालिसी होती है उसका नरुबुलएन यही होना चाहिए कि वह सिर्फ और सिर्फ आवाम की फला हो बहबूद के लिए हो, आवाम के वेलफेयर के लिए ही होनी चाहिए । आप देखेंगे कि सबसडीज के सिस्टम को या तो बिल्कुल खत्म किया जाए या सब्सडीज को कम से कम कर दिया गया जिसके नतीजे आज हम देख रहे हैं कि गरीब लोग इंतहाई मुसीबतों का सामना कर रहा है । आप यह देखिए कि फर्टिलाइजर पर सब्सडी खत्म करने की वजह से हमारे मुल्क का जो गरीब किसान है वह इस काबिल नहीं है कि खातिरखा यानी कि जितनी फर्टिलाइजर होनी चाहिए खेत में डालने के लिए उतनी वह खरीद नहीं सकता । लिहाजा जब वह फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो जाहिर है कि उसकी पैदावार पर भी काफी असर पड़ेगा । आज देखें कि हमारे पास, हमारे मुल्क में गेहूं की क्या कीमत है, हमारे मुल्क में चावल की क्या कीमत है । आज कोई चावल तीन-पांच-छः रुपये प्रति किलो से कम बाजार में नहीं मिलता है । अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो गेहूं की कीमत भी पांच या छः रुपये प्रति किलो से कम आपको नहीं मिलता है । इससे हटकर ऑयल सीड्स की जो कीमतें हैं, वह आसमान से बातें कर रही हैं । आज से तीन-चार पहले खुर्दनी तेल की जो कीमत थी यानी खाने के तेल की, उसकी कीमत आज दुगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है । इस वजह से ऑयल सीड्स की जो पैदावार है, वह एक तरफ तो बहुत कम होती चली जा रही है और हमारी जो जिराअती पोलिसी रही है वह इस काबिल नहीं रही कि हमारे मुल्क की जो जरुरियात हैं, उनको पेश-ए-नजर रखते हुए हमारी जिराअती पोलिसी का ताअय्युन नहीं किया गया है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी तिलहन की जो फसल है, वह इंतहाई गिरावट की तरफ है और खुर्दनी तेल की कीमतें आज एक दम आसमान से बातें कर रही हैं । इसी तरह से जनाब वाईस चेयरमैन साहब, मैं आपको बतलाऊं कि दालों की जो कीमतें हैं, वह क्या हैं ? उनकी कीमतें भी इंतहाई बढ़ी हुई हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क का किसान इस काबिल नहीं है कि वह खातिरखा और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सके । फिर आजकल जो पेस्टीसाइड्स की कीमतें हैं, हमारा गरीब किसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता । जब वह पेस्टीसाइड्स भी अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं कर सकता तो आप अन्दाजा लगाइये कि किस तरह से वह ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकता है । लिहाजा हम खाने के लिए गेहूं, चावल देखें, हम खुर्दनी या ऑयल सीड्स देखें और फिर उसी तरह से हमने दालों और तिलहन का भी सर्वे किया । इन तमाम चीजों के बावजूद आज हमको जरुरत क्या है ? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क की जो पोलिसी

prices ——

रही है, वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान क्या था, सेकेंड फाइव इयर प्लान क्या था ? कभी तो यह देखा गया कि सिर्फ जिराअात के ताल्लुक से एक दफे प्लान बनाया गया कभी तो यह देखा गया कि सिर्फ जिराअात के ताल्लुक से एक दफे प्लान बनाया गया था और इंडस्ट्रीज को बिल्कुल निगलेक्ट किया और जब यह आवाज पार्लियामेंट के एवाने और असेम्बली में चली कि जिरा-अात और इणडस्ट्री को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, तो हमारी हुकूमत एकदम पूरे तौर से इंडस्ट्री की तरफ तवोज्जह देने लगी, जिसका नतीजा यही हुआ कि जिरा-अात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। हालांकि हमारा मुल्क सारी दुनियां में सिर्फ जिराअात की वजह से जाना-पहचाना जाता है, इस वहजह से कि इस देश की 80 फीसदी आबादी पेश-ए-जिराअात पर कयरती है। लिहाजा जरुरत इस बात की है कि हम जिराअात के ताल्लुक से अच्छी और खातिरखा पौलिसी बनाएं।

चूंकि टाईम भी खत्म हो रहा है, मैं जनाब मोहम्मद अमीन साहब को मुबारक-बाद देता हूं कि उन्होंने वक्त की अहमत-रीन जरुरत महसूस करते हुए आज यह जो रिजोल्यूशन लाए हैं। मैं आपके तबस्सुत से हमारे वजीरे इफाइनेंस से दरखवास्त करूंगा कि आप जो बजट आगे दो-तीन महीने के अंदर लाने वाले नेहैं, वह इस किस्म का बजट बनाएं जो बिल्कुल हमारी कीमतों पर टिकाऊ कायम रहे और कीमतें बढ़ें नहीं, बल्कि कमी की तरफ कीमतों का रुझान हो।

شری محمد خلیل الرحمٰن "آندھرا پردیش": جناب وائس چیرمین صاحب۔ ہمارے معزز دوست اور ساتھی جناب محمد امین نے جو رزولیشن موو کیا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اس وجہ سے کہ اس صورتحال کی اصل ذمہ دار وہی حکومت ہوسکتی ہے۔ جو پچھلے ۴۵ برسوں میں سب سے زیادہ قریب قریب ۴۱ - ۴۰ سال تک اس ملک پر حکومت کرتی رہی۔ ظاہر ہے کہ اس حکومت کی جو اکانومک پالیسی رہی ہے۔ اس حکومت کی امپورٹ پالیسی۔ اس حکومت کی ایکسپورٹ پالیسی وہ سب ذمہ دار ہے کہ ہمارے ملک میں جو ضروری اشیاء ہیں مثال کے طور پر خوردنی تیل ہے اور اناج کی قیمتیں ہیں اور پھر پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ سب انہی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہیں کہ انکی قیمتیں دن پر دن بڑھتی جارہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی جو سوسائٹی ہے اس کا تصور جو ہے وہ سوشیلسٹک پیٹرن آف سوسائٹی ہے اور اس سوشیلسٹک پیٹرن آف سوسائٹی میں حکومت کی جو اکانومک پالیسی ہوتی ہے اس کا نصب العین یہی ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود کیلئے ہو۔ عوام کے دیلفیر کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ

کی جو ضروریات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری زراعتی پالیسی کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری توجہ کی جو فصل ہے وہ انتہائی گراوٹ کی طرف ہے اور خوردنی تیل کی جو قیمتیں آج ایک دم آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے جناب وائس چیئرمین صاحب میں آپ کو بتلاؤں کہ دالوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کیا ہیں ان کی قیمتیں بھی انتہائی بڑھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا کسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ خاطر خواہ اور فرٹیلائزر استعمال کر سکے۔ پھر آجکل جو پیسٹی سائڈس کی جو قیمتیں ہیں ہمارے غریب کسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ پیسٹی سائڈس بھی اپنے کھیتوں میں استعمال نہیں کر سکتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکتا ہے۔ لہذا ہم کھانے کے لیے گیہوں۔ چاول دیکھیں۔ ہم خوردنی یا آئیل سیڈس دیکھیں اور پھر اسی طرح سے ہم نے دالوں اور تلہن کا بھی سروے کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہم کو ضرورت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پالیسی رہی ہے وہ فرسٹ فائیو ایر پلان کیا تھا۔ کبھی تو یہ دیکھا گیا کہ صرف زراعت کے تعلق سے ایک دفعہ پلان بنایا

سبسڈیز کے سسٹم کو یا تو بالکل ختم کیا جائے یا سبسڈیز کو کم سے کم کر دیا گیا جس کے نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب لوگ انتہائی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ فرٹیلائزر پر سبسڈی ختم کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو غریب کسان ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ خواطر خواہ یعنی کہ جتنی فرٹیلائزر ہونی چاہیے کھیت میں ڈالنے کے لیے اتنی وہ خرید نہیں سکتا۔ لہذا جب وہ فرٹیلائزر استعمال نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کی پیداوار پر بھی کافی اثر پڑے گا۔ آج دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں گیہوں کی کیا قیمت ہے ہمارے ملک میں چاول کی کیا قیمت ہے۔ آج کوئی چاول تین۔ پانچ۔ چھ روپے پر فی کلو سے کم بازار میں نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ اوپن مارکیٹ میں جائیں تو گیہوں کی قیمت بھی پانچ یا چھ روپے پر فی کلو سے کم آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اس سے ہٹ کر آئیل سیڈ کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آج سے تین چار سال پہلے خوردنی تیل کی جو قیمت تھی یعنی کھانے کے تیل کی اس کی قیمت آج دوگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے آئیل سیڈس کی جو پیداوار ہے۔ وہ ایک طرف تو بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری جو زراعتی پالیسی رہی ہے وہ اس قابل نہیں رہی کہ ہمارے ملک

گیا تھا اور انڈسٹری کو بالکل نگلیکٹ کیا اور جب یہ آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں اور اسمبلی میں چلی کہ زراعت اور انڈسٹری کو بالکل نظرانداز کیا گیا تو ہماری حکومت ایک دم پورے طور سے انڈسٹری کی طرف توجہ دینے لگی۔ جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ زراعت کو پوری طرح سے نظرانداز کیا گیا۔ حالانکہ ہمارا ملک ساری دنیا میں صرف زراعت کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس دیش کی ۔۔ فیصد آبادی پیشہ زراعت کرتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زراعت کے تعلق سے اچھی اور خاطر خواہ پالیسی بنائیں۔

کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں جناب محمد امین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی اہم ترین ضرورت محسوس کرتے ہوئے آج یہ رزولیشن لائے ہیں۔ میں آپکے توسط سے ہمارے وزیر فائننس سے درخواست کروں گا کہ آپ جو بجٹ آگے دو تین مہینے کے اندر لانے والے ہیں وہ اس قسم کا بجٹ بنائیں جو بالکل ہماری قیمتوں پر رکاوٹ قائم رہے اور قیمتیں بڑھیں نہیں۔ بلکہ کمی کی طرف قیمتوں کا رجحان ہو۔

"ختم شد"

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : यहां बहुत अहम मुद्दे पर यह संकल्प उपस्थित किया गया था और पांच बजे तक का समय इसके लिए निर्धारित था। अब पांच बज गए हैं और हमें दूसरा विधेयक लेना है। जिन सदस्यों ने इस पर अपनी बात रखी हैं, पिछली बार भी जब बात हुई थी तो सरकार की तरफ से मंत्री महोदय ने इंटरवीन किया था लेकिन जब समय नहीं है . . . . (व्यवधान) . . . .

اپ سبھا ادھیکش "شری محمد سلیم" : یہاں بہت اہم مدعے پر یہ سنکلپ اپستھت کیا گیا تھا اور پانچ بجے تک کا سمے اس کے لیے نردھارت تھا۔ اب پانچ بج گئے ہیں اور ہمیں دوسرا ودھے یک لینا ہے۔ جن سدسیوں نے اس پر اپنی باتیں رکھی ہیں پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی تو سرکار کی طرف سے منتری مہودے نے انٹروین کیا تھا لیکن اب سمے نہیں ہے "مداخلت"

श्रीमती कमला सिन्हा : आधा घंटा बढा दिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मैं समझता हूं कि दूसरे विधेयक पर जाना है। पांच बजे तक का समय इसके लिए निर्धारित था। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मंत्री महोदय अवश्य उनका ध्यान रखेंगे, उन पर विचार करेंगे।

اپ سبھا ادھیکش : میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے ودھے یک پر جانا ہے۔ پانچ بجے تک کا سمے اس کے لیے نردھارت تھا۔ माननीय مانیہ سدسیوں نے جو باتیں کہی ہیں۔ منتری مہودے اوشیہ ان کا دھیان رکھیں گے۔ ان پر وچار کریں گے۔

श्रीमती कमला सिन्हा : 15-20 मिनट का समय दे देते, मंत्री जी बोल देते । हम रोग मंत्री जी के मुखारबिंद की तरफ देख रहे हैं । ख

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : महंगाई के मुद्दे पर जब बात हो रही थी, हम अगर समय इतना महंगा नहीं करते तो इसको कनक्लूडिंग स्तर पर ले जा सकते थे ।

اپ سبھا ادھیکش : مہنگائی کے مدعے پر جب بات ہو رہی تھی، ہم اگر سمے اتنا مہنگا نہیں کرتے تو اس کو کنکلوڈنگ استر تک لے جا سکتے تھے۔

(I) STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 1992

II THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1992

III. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DENTISTS (AMENDMENT) ORDINANCE 1992

IV. THE DENTISTS (AMENDMENT) BILL, 1992

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The statutory resolutions disapproving the Indian, Medical Council (Amendment) Ordinance, 1992, and the Dentists (Amendment) Ordinance, 1992,, and the Bills replacing the Ordinances will be taken up together.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Sir, I move the following resolutions:

1. "That this House disapproves the Indian Medical Council (Amend ment) Ordinance, 1992 (No. 13 of 1992) promulgated by the President on the 27th August, 1992."
2. "That this House disapproves the Dentists (Amendment) Ordinance, 1992 (No. 14 of 1992) promulgated by the President on the 27th August, 1992."

Sir, I would like to read a portion from the debates of the Constituent Assembly for the benefit of my hon. friend.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Have you moved both the resolutions?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Yes. Can I now explain why I moved these resolutions?

I am reading a portion from the Con*-tituent Assembly debates, Volume 8, Page 213 in which Dr. Ambedkar said that the ordinance-making power was to be exercised in cases

"where the powers conferred by the ordinary law existing at any particular moment may be deficient to deal with the situation which may suddenly or immediately arise.* Sir, I want to make a case here that the Government has abused the President's powers to issue ordinances under article 123 of the Constitution. It is a panicking and ill advised response to a problem that needs a deeper understanding and analysis Let me explain. The Government has not done its business properly. The Members of this hon. House know that in the Rajya Sabha, a Bill was introduced by the then Minister if Health on 26.8.1987 which was also for amending the Indian Medical Council (Amendment) Act. Sir, that (Bill had a provision which is included in this Bill also that any medical college, before it is opened, will have to take the prior sanction of the Medical Council of India. That Bill which was introduced in the Rajya Sabha on 26.8.87 was referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament on 14.12.1987 and that Joint Committee of Parliament deliberated on this issue, gave its opinion and submitted a report on 28.7. 1989. This report, with the opinion of both Houses of Parliament, was in the possession of the Government.

† []Transliteratiori in Arabic Script.